

न्यू इंडिया समाचार



ई-कॉपी के लिए
QR स्कैन करें



समृद्ध भारत, सशक्त किसान

कृषि क्षेत्र की मजबूती ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है। सशक्त किसान न केवल अपनी समृद्धि सुनिश्चित करता है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और आर्थिक स्थिरता में भी देता है योगदान...



पंडित दीनदयाल उपाध्याय

11 फरवरी पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन

अंत्योदय के प्रणेता

संपूर्ण जीवन का आधार सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को बनाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ और निधन 11 फरवरी 1968 को हुआ। उनके विचार व कर्तव्यनिष्ठा से भारतीय राजनीति में अद्वितीय आदर्श स्थापित किए। उनका एकात्म मानववाद का दर्शन भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की समस्याओं के समाधान में भी सक्षम है। उन्होंने अंत्योदय का सपना देखा, वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना, अंतिम पंक्ति में खड़े 'अंतिम व्यक्ति' के चेहरे की मुस्कान से मापा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंत्योदय को संतुष्टिकरण का विस्तार दिया। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विजन के साथ बीते 11 वर्षों से हो रहा है न्याय...



पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर हम उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। वह दूरदर्शी विचारक थे। उन्होंने खुद को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान का उनका दर्शन एक मजबूत राष्ट्र की ओर हमारी यात्रा को प्रेरित करता है। प्रगति और एकता के लिए उनका बलिदान और आदर्श हमारे सामूहिक मिशन में एक मार्गदर्शक शक्ति बने हुए हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



प्रधान संपादक

धीरेन्द्र ओझा

प्रधान महानिदेशक

पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक

संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक

पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक

अखिलेश कुमार

चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन

सुमित कुमार (अंग्रेजी)

रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)

नदीम अहमद (उर्दू)

सीनियर डिजाइनर

फूलचंद तिवारी

डिजाइनर

अभय गुप्ता

सत्यम सिंह



13 भाषाओं में उपलब्ध
न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने
के लिए क्लिक करें।

<https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx>

न्यू इंडिया समाचार के पुराने
अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

<https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx>



न्यू इंडिया समाचार के बारे में
लगातार अपडेट के लिए फॉलो
करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

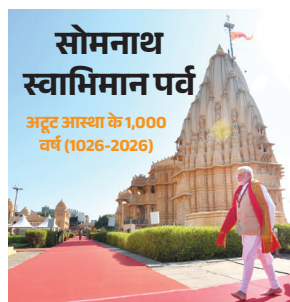


आवरण कथा

कृषि व किसान कल्याण

आज बीज से बाजार तक सरकार के लिए देश के अन्नदाता किसानों का हित सर्वोच्च संकल्प बन गया है, क्योंकि विकसित भारत के निर्माण में किसानों की बड़ी भूमिका है। इसलिए किसानों को सुदृढ़ बनाने के लिए बुवाई से पहले, बुवाई के दौरान और बुवाई के बाद के सभी चरणों में योजना, नीति और पहल से रखा जा रहा है ध्यान... | 14-27

प्रधानमंत्री का विशेष आलेख



सोमनाथ मंदिर पर पहले आक्रमण के 1,000 वर्ष पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ है। इस विषय पर प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आलेख... | 8-11

प्रधानमंत्री का विशेष आलेख

एक भारत, श्रेष्ठ भारत का जीवंत प्रतीक है काशी-तमिल संगमम



काशी-तमिल के सामाजिक और संस्कृतिक महत्व को लेकर काशी-तमिल संगमम पर पढ़ें पीएम मोदी का विशेष आलेख... | 54-56

समाचार सार

| 4-5

व्यक्तित्व : तिलका मांझी

| 6

संथाल विद्रोह के नायक

ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज 'BRICS'

| 7

भारत की अध्यक्षता वाली 'ब्रिक्स 2026' की वेबसाइट, थीम व लोगो लॉन्च

अखंड सोमनाथ, समृद्ध विरासत

पीएम मोदी बोले- एक हजार साल बाद भी सोमनाथ पर लहरा रहा है ध्वज | 12-13

नीति से नवाचार तक युवाओं की निर्णायक भागीदारी

यंग लीडर्स डायलॉग-2026 को पीएम मोदी ने किया संबोधित | 28-29

भारत को लेकर वैश्विक संस्थाएं 'बुल्लिश'

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का संबोधन | 30-31

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, भारत की सौर क्रांति

योजना के दो वर्ष : 21 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगे | 32-33

'आत्मनिर्भर भारत' की पटरी पर दौड़ती 'वंदे भारत एक्सप्रेस'

7.5 करोड़ से अधिक यात्री वंदे भारत ट्रेन से यात्रा का ले चुके हैं लाभ | 34-36

संतुलन का खेल है 'वॉलीबॉल'

72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन | 37

पूर्वांचल के मंत्र का सारथी बन रहा पश्चिम बंगाल

पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी 4,080 करोड़ रुपये की सौगातें | 38-39

इकोनोमी और इकोलॉजी का नया अध्याय लिख रहा असम

पीएम मोदी ने काजीरंगा के लिए विशेष परियोजना की शुरुआत की | 40-41

पूरी मानवता को भगवान बुद्ध का ज्ञान

पीएम मोदी ने पिपरहवा के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का किया उद्घाटन | 42-43

भारत ने विविधता को बना दिया लोकतंत्र की ताकत

पीएम मोदी ने राष्ट्रमंडल देशों के 28वें सीएसपीओसी का किया उद्घाटन | 44-45

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस उत्सव

प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों से की बातचीत | 46-47

गणतंत्र दिवस...स्वाधीनता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्य का प्रतीक

77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन | 48-49

शौर्य, सामर्थ्य और संस्कृति के साथ गुंजा 'वंदे मातरम्'

77वें गणतंत्र दिवस समारोह की झलकियां | 50-53

सहयोग से सशक्त होती भारत-जर्मनी भागीदारी

जर्मन चांसलर की दो दिवसीय भारत यात्रा | 57-58

संपादक की कलम से...

भारत का अन्नदाता, विकास यात्रा का सशक्त विधाता

सादर नमस्कार।

भारत का किसान यानी अन्नदाता, आज केवल खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह देश की विकास यात्रा का सक्रिय और भरोसेमंद साथी बन चुका है। विकसित भारत में सहयात्री बने किसान परिवारों ने न केवल देश बल्कि जरूरत पड़ने पर विश्व का भरण-पोषण किया है।

आज भारत विश्व में चावल, दलहन, दूध समेत कई कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके पीछे वर्षों की निरंतर मेहनत, नीतियों को लेकर स्पष्ट दिशा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का योगदान है, जिसने भारतीय कृषि की संभावनाओं को नए आयाम दिए। बीज से लेकर बाजार तक के इस सफर में भारत ने वैश्विक संकटों, महामारी और आपदा जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपनी उत्पादन क्षमता में लगातार वृद्धि दर्ज की है।

पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार से समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है, उसने किसान को व्यवस्था के केंद्र में लाकर खड़ा किया है। आज किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। आर्थिक सहयोग के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से नियमित सहायता पहुंचाई जा रही है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भी संबल मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की सुरक्षा कवच बनी है। कृषि अवसंरचना निधि से कृषि इंफ्रा को मजबूती मिल रही है। डिजिटल माध्यमों और राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी पहल ने किसानों को पारदर्शी और व्यापक बाजार से जोड़ा है।

केंद्र सरकार ने परंपरागत खेती के अलावा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और प्राकृतिक खेती जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देकर किसानों की आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित किए हैं।

विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब कृषि सशक्त और किसान समृद्ध हो। अन्नदाता की मेहनत, नीति की स्पष्टता और तकनीक के समन्वय से आज भारतीय कृषि एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है।

इस 1 फरवरी को किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने वाले सबसे बड़े कदम- पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी संदर्भ में कृषि व किसान कल्याण की 11 वर्ष की परिवर्तनकारी यात्रा ही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में संधाल विद्रोह के नायक तिलका मांझी, फ्लैगशिप में पीएम सूर्य घर योजना, वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता की कहानी, सोमनाथ और काशी-तमिल संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आलेख सहित पखवाड़े भर के उनके कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर 11 फरवरी को अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन और बैंक कवर पर 1 फरवरी 2026 को भारतीय तटरक्षक बल के 50वें स्थापना दिवस पर विशेष सामग्री समाहित है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहें।

(धीरेन्द्र ओझा)



हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
<https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx>

आपकी बात...



जानकारी और जन जागरूकता का एक उपयोगी स्रोत

हाल ही में एक पुस्तकालय में मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ने को मिली। यह बहुत ही जानकारीपरक पत्रिका है। इस पत्रिका में जानकारी और जन जागरूकता का एक उपयोगी स्रोत बनने की क्षमता है। यह ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक पहुंच रही है।

arunendu.k11@gmail.com

सोशल स्कीम के बारे में जानने का बहुत अच्छा जरिया

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका हर तरह के लोगों के लिए अलग-अलग सोशल स्कीम और देश के लिए जरूरी कार्यक्रमों को जानने का एक बहुत अच्छा जरिया है। यह लोगों को सरकार से जोड़ती है और प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को पाने के हमारे इरादे को मजबूत करती है।

सौरव शर्मा

sharmasourav1261@gmail.com

साफ, अच्छी तरह से व्यवस्थित और समझने में आसान

मुझे न्यू इंडिया समाचार एक आशाजनक और जानकारी देने वाली पत्रिका लगी। यह नागरिकों को सरकारी पहलों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जोड़ने की कोशिश करती है। इसका कंटेंट साफ, अच्छी तरह से व्यवस्थित और समझने में आसान लगता है। इसमें प्रकाशित आलेख नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को सरल भाषा में समझाते हैं। इससे पहली बार पढ़ने वालों को बिना ज्यादा मेहनत के मुश्किल मुद्दों को समझने में मदद मिलती है। पाठकों को राष्ट्रीय प्रयासों की जानकारी मिलती है। प्रगति और सार्वजनिक सेवा से जुड़े आलेख पत्रिका का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं।

ए. मायिलसामा

myilsamia@gmail.com

आगे बढ़ता रहे न्यू इंडिया समाचार

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का अंक पढ़ने को मिला। यह बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इस अंक में इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर पेंटर नंदलाल बसु के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल पढ़कर मुझे बहुत सी अनजानी जानकारी मिली। जब मैं सोचता हूँ कि उन्होंने संविधान के हर हिस्से को पेंट किया है तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के 'वंदे मातरम' पर लिखे आर्टिकल ने भी मेरा दिल छू लिया। इस अंक का सबसे जरूरी आर्टिकल 'कोऑपरेटिव - एक खुशहाल समाज का निर्माण' है। कोऑपरेटिव मूवमेंट पर लिखी गई यह लंबी रिपोर्ट मुझ जैसे पाठकों तक पहुंची है। न्यू इंडिया समाचार इसी तरह आगे बढ़ता रहे।

mangalprasadmaity@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003.
ईमेल- response-nis@pib.gov.in



न्यू इंडिया समाचार को आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर शनिवार-रविवार को दोपहर 3:10 से 3:25 बजे तक सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।



नए फास्टैग वाली कारों के लिए अब नहीं करानी होगी केवाईवी

आप 1 फरवरी, 2026 के बाद कार/जीप या वैन श्रेणी का नया फास्टैग लेते हैं तो अब आपको 'नो योर व्हीकल' यानी केवाईवी कराने की जरूरत नहीं होगी। सार्वजनिक सुविधा बढ़ाने और राजमार्गों का उपयोग करने वाले लोगों को सक्रिय किए जाने के बाद होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे बंद करने का फैसला किया है। कारों के लिए पहले से जारी यानी मौजूदा फास्टैग के लिए अब केवाईवी रूटीन जरूरत के तौर पर अनिवार्य नहीं होगा। यह सुधार अनुपालन को मजबूत करेंगे और शिकायतों में कमी भी लायेंगे। सक्रिय किए जाने से पहले सत्यापन की पूरी जिम्मेदारी जारीकर्ता बैंकों को सौंपकर, एनएचआई का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले लोगों को परेशानी से मुक्त अनुभव प्रदान करना है।

फास्टैग एक्टिव करने से पहले सुरक्षा के ठोस उपाय

- **अनिवार्य वाहन-आधारित सत्यापन**
फास्टैग को एक्टिव करने की अनुमति केवल वाहन डेटाबेस से वाहन के विवरण के सत्यापन के बाद ही दी जाएगी।
- **फास्टैग एक्टिव होने के बाद कोई सत्यापन नहीं:** सत्यापन की अनुमति देने वाला पहले का प्रावधान बंद कर दिया गया है।
- **असाधारण मामलों में आरसी-आधारित सत्यापन**
वाहन विवरण वाहन पर उपलब्ध नहीं है, वहां जारीकर्ता बैंकों को पूरी जवाबदेही के साथ फास्टैग एक्टिव करने से पहले आरसी विवरण को सत्यापित करना होगा।
- **ऑनलाइन फास्टैग शामिल:** ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से बेचे जाने वाले फास्टैग भी बैंकों द्वारा पूर्ण सत्यापन के बाद ही सक्रिय किए जाएंगे।



भारत की जनगणना 2027 मकान सूचीकरण से पहले मिलेगा स्व-गणना का विकल्प

भारत की जनगणना 2027 कई मामलों में अलग होगी जिसके प्रथम चरण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच निर्धारित 30 दिनों की अवधि में किया जाएगा। मकान सूचीकरण से पहले प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार जनगणना इतिहास में पहली बार 15 दिनों की अवधि के दौरान स्व-गणना का विकल्प होगा। इस दौरान नागरिक एक निश्चित डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी जानकारी भर सकेंगे जिससे प्रक्रिया तेज होगी। भारत की जनगणना 2027 में पहली बार डिजिटल माध्यम से होगी। डेटा संग्रह मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग होगा जिससे जनगणना 2027 का डेटा पूरे देश में कम से कम समय में उपलब्ध हो सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना में जाति डेटा को



इलेक्ट्रॉनिक रूप से शामिल करने की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। जनगणना 2027, देश में 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी।

एनएच-544जी निर्माण में बने चार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपनी इंजीनियरिंग काबिलियत और शानदार काम के दम पर एनएच-544जी 6-लेन राष्ट्रीय हाईवे परियोजना के अंतर्गत दुनिया भर में पहली निर्माण कंपनी के साथ मिलकर एक या दो नहीं बल्कि चार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं।

एनएचएआई ने 6 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी के पास दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला, बिटुमिनस कंक्रीट को लगातार बिछाने का सबसे लंबा रिकॉर्ड था, जिसमें 24 घंटे के अंदर 28.89 लेन किलोमीटर या 3-लेन चौड़े 9.63 किलोमीटर लंबे खंड को कवर किया गया। दूसरा रिकॉर्ड 24 घंटे में 10,655 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट की सबसे अधिक मात्रा को लगातार बिछाने के लिए बनाया गया।

इसी कड़ी में 11 जनवरी 2026 को दो और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। इनमें 57,500 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट को लगातार बिछाना और 156 लेन किलोमीटर या 3-लेन चौड़े 52 किलोमीटर लंबे सेक्शन की लगातार पेविंग का रिकॉर्ड शामिल है, जिसने बीते विश्व रिकॉर्ड 84.4 लेन किलोमीटर या 2-लेन चौड़े 42.2 किलोमीटर लंबे खंड को पीछे छोड़ दिया। ये रिकॉर्ड बनाने वाले काम बैंगलुरु-कडप्पा-विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे के पैकेज-2 और पैकेज-3 में किए गए।

• 24 घंटे में **28.89** लेन किलोमीटर तक लगातार बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का सबसे लंबा रिकॉर्ड

• 24 घंटे में **10,655** मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट की सबसे अधिक मात्रा लगातार बिछाने का रिकॉर्ड

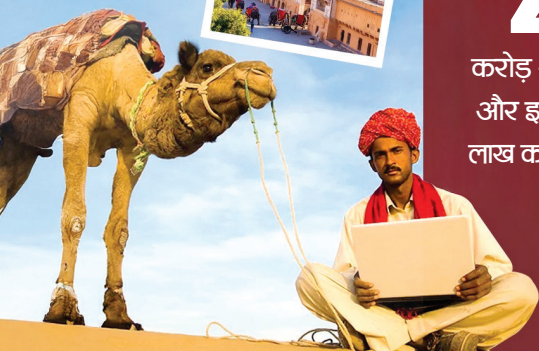
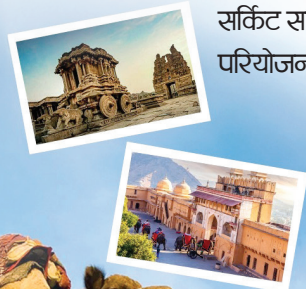
57,500 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट लगातार बिछाने का रिकॉर्ड

156 लेन किलोमीटर लगातार पक्की सड़क बनाने का रिकॉर्ड



स्वदेश दर्शन योजना: एक दशक में 110 से अधिक प्रोजेक्ट विकसित

“पर्यटन क्षेत्र में अनेक लोगों के जीवन में समृद्धि लाने की क्षमता है। केंद्र सरकार भारत के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अतुल्य भारत के अद्भुत अनुभवों का आनंद ले सकें।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यटन क्षेत्र को लेकर इसी प्रतिबद्धता का नतीजा है कि बीते एक दशक में स्वदेश दर्शन और स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत, रामायण, बौद्ध, तटीय और जनजातीय सर्किट सहित विभिन्न विषयगत सर्किटों में 110 परियोजनाएं विकसित की गई हैं।



वर्ष 2024 के दौरान भारत में

2.057

करोड़ अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए और इस दौरान पर्यटन से 2.93 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा में उपलब्धि 50 हजार स्वास्थ्य केंद्र प्रमाणित

भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर कर रही है। इस दिशा में स्वास्थ्य केंद्रों का न सिर्फ विस्तार किया जा रहा है बल्कि आधुनिक और उन्नत सुविधाओं से लैस भी किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि 31 दिसंबर 2025 तक, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 50,373 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएस) के तहत प्रमाणित किया गया है। यह गुणवत्ता, सुरक्षा और रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एनक्यूएस की शुरुआत वर्ष 2015 में मात्र 10 प्रमाणित स्वास्थ्य केंद्रों के साथ हुई थी जो दिसंबर 2025 तक यह आंकड़ा 50,373 तक पहुंच गई है। यह एक वर्ष के भीतर हुई तीव्र वृद्धि को दर्शाती है। इसमें 48,663 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 1,710 द्वितीयक देखभाल सुविधाएं शामिल हैं।





संथाल विद्रोह के नायक

संथाल आदिवासी तिलका मांझी ने 1857 की लड़ाई से तकरीबन 80 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ धनुष बाण के दम पर ही विद्रोह छेड़ दिया था। उन्होंने आदिवासियों को एक सेना के रूप में संगठित किया और 1784 में प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने समुदाय के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोषागार पर छापा मार दिया था जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय दिया बल्कि संघर्ष से संपूर्ण भारत को स्वतंत्रता हासिल करने के लिए किया प्रेरित...

■ जन्म: 11 फरवरी 1750 ■ शहीदी दिवस : 13 जनवरी 1785

भारत का अतीत, इतिहास, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। देश की आजादी की लड़ाई का पग-पग, इतिहास का पन्ना-पन्ना आदिवासी वीरता से भरा पड़ा है। ऐसे ही एक नायक थे तिलका मांझी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ज्यादतियों के खिलाफ संघर्ष किया और विदेशी हुकूमत के खिलाफ संग्राम का बिगुल फूंक दिया। वो भी तब जब अंग्रेजों के खिलाफ कहीं कोई विद्रोह की बात नहीं हो रही थी। 1857 की क्रांति से भी पहले 1784 में संथाल में उनके नेतृत्व में 'दामिन सत्याग्रह' लड़ा गया था। वह ऐसा समय था जब अंग्रेज किसी न किसी तरह से अपना विस्तार करते जा रहे थे। मां भारती को धीरे-धीरे जंजीरों के बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास कर रहे थे।

11 फरवरी 1750 को बिहार में भागलपुर के सुल्तानगंज में एक संथाल परिवार में जन्मे तिलका मांझी ने अपने बहादुरी के दम पर न केवल अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया बल्कि अंग्रेजी शासकों को जीते जी कभी चैन की नींद सोने नहीं दिया। मांझी का असल नाम जाबरा पहाड़िया बताया जाता है। कहते हैं कि तिलका नाम उन्हें अंग्रेजों ने दिया था। एक बार एक अंग्रेज ने इनकी घूरती लाल आंखों में देखा था। दरअसल पहाड़िया भाषा में 'तिलका' का अर्थ गुस्सैल और लाल-लाल आंखों वाला व्यक्ति होता है। दस्तावेजों में यह उनकी पहचान बन गई और इतिहास में तिलका नाम अमर हो गया। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले तिलका मांझी ने अंग्रेजों के सामने कभी भी समर्पण नहीं किया। न ही कभी झुके और न ही डरे।

उन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूँका

था बल्कि उन्होंने स्थानीय सूदखोरों-जमींदारों के खिलाफ भी मुहिम छेड़ी थी। 1778 में उन्होंने पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैप को अंग्रेजों से मुक्त करवाया। 1784 में राजमहल के मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड को मार डाला। इसके बाद अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज उन्हें घोड़े से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर ले गए। 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के चौराहे पर एक विशाल वटवृक्ष में लटका कर फांसी दे दी। यही वजह है कि तिलका मांझी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है।

तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है। साथ ही बांग्ला की सुप्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी ने उनके जीवन और विद्रोह पर बांग्ला भाषा में एक उपन्यास 'शालगिरर डाके' की रचना की है जिसे हिंदी में 'शालगिरह की पुकार पर' नाम से अनुवादित और प्रकाशित किया गया है। 29 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तिलका मांझी को याद किया था। उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। इसी भारत भूमि पर महान तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ बिगुल फूँका था। साथ ही 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में विकास कार्यों के शुभारंभ अवसर पर भी उन्होंने कहा था कि इस धरती में आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। ये शहीद तिलका मांझी की धरती है, ये सिल्क सिटी भी है। इतना ही नहीं उन्होंने अन्य अवसरों पर भी तिलका मांझी को श्रद्धापूर्वक नमन किया है। ■

ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज 'BRICS'

भारत की अध्यक्षता में BRICS 2026

जी-20 जैसी प्रभावशाली संस्था हो या वर्ष 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान (अंतरराष्ट्रीय आईडीईए) की अध्यक्षता, भारत ने पिछले एक दशक में वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। अब इस कड़ी में एक नई उपलब्धि और जुड़ने वाली है। भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है। इसके लिए विदेशी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 'ब्रिक्स 2026' की वेबसाइट, थीम और लोगो किया लॉन्च...

वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर BRICS सहयोग का एक अहम मंच है। यह ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को मजबूती देता है। दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स का वैश्विक जीडीपी में करीब 40% का योगदान है। भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली ब्रिक्स का थीम- 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और विकास के लिए निर्माण' रखा गया है।

ब्रिक्स के चार प्रमुख स्तंभ

- **लचीलापन** : वैश्विक आपूर्ति-शृंखला, स्वास्थ्य और जलवायु जोखिमों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना।
- **नवाचार** : सेवा वितरण और विकास के लिए **DPI**, फिनटेक, **AI** और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना।
- **सहयोग** : नीति, वित्त, व्यापार, शासन सुधार और जन-भागीदारी में **BRICS** देशों के बीच समन्वय को मजबूत करना।
- **सततता** : जलवायु कार्बन, हरित वित्त, ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास को गति देना।

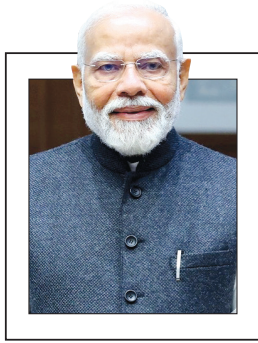
ब्रिक्स 2026 की आधिकारिक वेबसाइट btovd2026.gov.in को विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 13 जनवरी को लॉन्च की। इस बार सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की आवाज को और मजबूत करने पर बात होगी, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, जिम्मेदार एआई इनोवेशन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। ब्रिक्स दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाता है। मूल सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। नए शामिल देशों में सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया हैं।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर 'मानवता प्रथम' और 'जन-केंद्रित' दृष्टिकोण के साथ अपनी अध्यक्षता कर रहा है। सम्मेलन के इस बार का विषय यह विश्वास दर्शाता है कि 'ब्रिक्स' सदस्यों के बीच सहयोग साझा चुनौतियों का संतुलित और समावेशी तरीके से समाधान करने में मदद कर सकता है। यह विषय सभी के लाभ के लिए क्षमताओं को मजबूत करने, नवाचार को बढ़ावा देने और सतत विकास सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है। ■



सोमनाथ स्वाभिमान पर्व

अटूट आस्था के 1000 वर्ष (1026-2026)



नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन में जो भी पुण्य कामनाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है।



प्रधानमंत्री का आलेख पढ़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।

वर्ष 2026, सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। सदियों से बार-बार हुए हमलों के बावजूद, सोमनाथ मंदिर भारत की अटूट भावना के प्रतीक के रूप में आज भी शान से खड़ा है। सोमनाथ की कथा केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि भारत माता के उन अनगिनत सपूतों के अदम्य साहस की कहानी है जिन्होंने देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की। जनवरी 1026 में सोमनाथ पर पहला आक्रमण हुआ था, जिसके 1 हजार वर्ष पूरे हो रहे हैं तो यह वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी साक्षी है। इस जनवरी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ है। इस विषय पर प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित आलेख...

सोमनाथ... ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में, प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ, भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता है... “सौराष्ट्रे सोमनाथं च... यानि ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। ये इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है:

“सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ।
लभते फलं मनोवाञ्छितं मृतः स्वर्गं समाश्रयेत् ॥”

अर्थात्, सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन में जो भी पुण्य कामनाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है।

दुर्भाग्यवश, यही सोमनाथ, जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र था, विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था। वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इस महान



संयोग से 2026 सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण सम्पन्न हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे।

तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था, इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था।

सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। फिर भी, एक हजार वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। साल 1026 के बाद समय-समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुनःनिर्मित करने के प्रयास जारी रहे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण संपन्न हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे।

1026 में एक हजार वर्ष पहले सोमनाथ पर हुए पहले

आक्रमण, वहां के लोगों के साथ की गई क्रूरता और विध्वंस का वर्णन अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है तो हृदय कांप उठता है। हर पंक्ति में क्रूरता के निशान मिलते हैं, ये ऐसा दुःख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है।

हम कल्पना कर सकते हैं कि इसका उस दौर में भारत पर और लोगों के मनोबल पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। सोमनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा था। ये बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचता था। ये एक ऐसे समाज की प्रेरणा था जिसकी आर्थिक क्षमता भी बहुत सशक्त थी। हमारे समुद्री व्यापारी और नाविक इसके वैभव की कथाएं दूर-दूर तक ले जाते थे।

सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है, ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है।

1026 में शुरू हुई मध्यकालीन बर्बरता ने आगे चलकर दूसरों को भी बार-बार सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। यह हमारे लोगों और हमारी संस्कृति को गुलाम बनाने का प्रयास था। लेकिन हर बार जब मंदिर पर आक्रमण हुआ, तब हमारे पास ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थीं जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए खड़े होकर सर्वोच्च बलिदान दिया।

हर बार, पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे पुनः जीवंत किया।

महमूद गजनवी लूटकर चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। सोमनाथ से जुड़ी हमारी आस्था, हमारा विश्वास और प्रबल हुआ। उसकी आत्मा लाखों श्रद्धालुओं की भीतर सांस लेती रही। साल 1026 के हजार साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है, वो आज भी हमारी शक्ति का पुंज है।

ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उस धरती पर जीवन पाया है, जिसने देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति को जन्म दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का पुण्य प्रयास किया कि श्रद्धालु सोमनाथ में पूजा कर सकें।

1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद भी सोमनाथ आए थे, वो अनुभव उन्हें भीतर तक आंदोलित कर गया। 1897 में चेन्नई में दिए गए एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा, “दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर और गुजरात के सोमनाथ जैसे मंदिर आपको ज्ञान के अनगिनत पाठ सिखाएंगे। ये आपको किसी भी संख्या में पढ़ी गई पुस्तकों से अधिक हमारी सभ्यता की गहरी समझ देंगे।

इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों के निशान हैं और सैकड़ों बार इनका पुनर्जागरण हुआ है। ये बार बार नष्ट किए गए, और हर बार अपने ही खंडहरों से फिर खड़े हुए। पहले की तरह सशक्त। पहले की तरह जीवंत। यही राष्ट्रीय मन है,

यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। इसका अनुसरण आपको गौरव से भर देता है। इसको छोड़ देने का मतलब है, मृत्यु। इससे अलग हो जाने पर विनाश ही होगा।”

ये सर्वविदित है कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभभाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। उन्होंने आगे बढ़कर इस दायित्व के लिए कदम बढ़ाया। 1947 में दीवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, उसी समय उन्होंने घोषणा की कि यहीं सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अंततः 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए।

उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था।





1000 वर्ष बाद 2026 में भी सोमनाथ का समुद्र उसी तीव्रता से गर्जना करता है। तट को स्पर्श करती लहरें उसकी पूरी गाथा सुनाती हैं। उन लहरों की तरह सोमनाथ बार-बार उठता रहा है।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ, उसने एक नया इतिहास रच दिया।

सोमनाथ मंदिर का कोई भी उल्लेख के.एम. मुंशी जी के योगदानों को याद किए बिना अधूरा है। उन्होंने उस समय सरदार पटेल का प्रभावी रूप से समर्थन किया था। सोमनाथ पर उनका कार्य, विशेष रूप से उनकी पुस्तक 'सोमनाथ, द श्राइन इटर्नल', अवश्य पढ़ी जानी चाहिए।

जैसा कि मुंशी जी की पुस्तक के शीर्षक से स्पष्ट होता है, हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो आत्मा और विचारों की अमरता में अटूट विश्वास रखती है। हम विश्वास करते हैं- नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। सोमनाथ का भौतिक ढांचा नष्ट हो गया लेकिन उसकी चेतना अमर रही।

इन्हीं विचारों ने हमें हर कालखंड में, हर परिस्थिति में फिर से उठ खड़े होने, मजबूत बनने और आगे बढ़ने का सामर्थ्य दिया है। इन्हीं मूल्यों और हमारे लोगों के संकल्प की वजह से आज भारत पर दुनिया की नजर है। दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। वो हमारे इनोवेटिव युवाओं में निवेश करना चाहती है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारा संगीत और हमारे अनेक पर्व आज वैश्विक पहचान बना रहे हैं। योग और आयुर्वेद जैसे विषय पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रहे हैं। ये स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं। आज कई वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है।

अनादि काल से सोमनाथ जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ता आया है। सदियों पहले जैन परंपरा के आदरणीय मुनि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य यहां आए थे और कहा जाता है कि प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा, “भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याः क्षयमुपगता यस्य। अर्थात्, उस परम तत्त्व को नमन जिसमें सांसारिक बंधनों के बीज नष्ट हो चुके हैं। जिसमें राग और सभी विकार शांत हो गए हैं।

आज भी दादा सोमनाथ के दर्शन से ऐसी ही अनुभूति होती है। मन में एक ठहराव आ जाता है, आत्मा को अंदर तक कुछ स्पर्श करता है, जो अलौकिक है, अव्यक्त है।

1026 के पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद 2026 में भी सोमनाथ का समुद्र उसी तीव्रता से गर्जना करता है और तट को स्पर्श करती लहरें उसकी पूरी गाथा सुनाती हैं। उन लहरों की तरह सोमनाथ बार-बार उठता रहा है।

अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल बन चुके हैं। उनका नाम अब विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। इतिहास के पन्नों में वे केवल फुटनोट हैं, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है। सोमनाथ हमें ये बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। ये विश्वास का वो स्वर है, जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है।

अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए, इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक नए संकल्प के साथ, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। एक ऐसा भारत, जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है।

जय सोमनाथ ! ■

अखंड सोमनाथ समृद्ध विरासत

सोमनाथ केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत निरंतरता का प्रकाश स्तंभ है, जो अपनी आस्था, अटूट जीवटता और एकता के संदेश से पीढ़ियों को प्रेरित करता आ रहा है। गुजरात में 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक हजार साल बाद भी सोमनाथ मंदिर पर ध्वज लहरा रहा है जो दुनिया को भारत की ताकत और भावना की दिलाता है याद...

गजनी से लेकर औरंगजेब तक जब तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो समझ नहीं पाये कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात् अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदाशिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है जो कल्याणकारक भी है और शक्ति का स्रोत भी। गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए आततायी आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमटकर रह गए हैं। और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म-ध्वजा को थामे खड़ा है। सोमनाथ का ये शिखर मानो उद्घोष कर रहा है- चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ! अर्थात्, मैं चंद्रशेखर शिव पर आश्रित हूँ, काल भी मेरा क्या कर लेगा !

आज का भारत विरासत से विकास की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है। सोमनाथ में विकास भी विरासत भी, ये भावना निरंतर



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

सोमनाथ मंदिर दृढ़ता, आस्था और राष्ट्रीय गौरव का एक सशक्त प्रतीक

- सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी 2026 तक सोमनाथ में आयोजित किया गया।
- यह पर्व भारत के उन असंख्य नागरिकों की स्मृति में मनाया गया, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया और जो आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रेरित करते रहेंगे।
- यह कार्यक्रम 1026 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया।
- सदियों से इसे नष्ट करने के कई प्रयासों के बावजूद, सोमनाथ मंदिर आज भी दृढ़ता, आस्था और राष्ट्रीय गौरव का एक सशक्त प्रतीक है। यह प्राचीन वैभव में पुनर्स्थापित करने के सामूहिक संकल्प और प्रयासों का परिणाम है।
- स्वतंत्रता के बाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास किया।
- इस पुनरुद्धार यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 1951 में हासिल हुई, जब जीर्णोद्धार किए गए सोमनाथ मंदिर को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में भक्तों के लिए औपचारिक रूप से खोला गया।
- 2026 में इस ऐतिहासिक जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का महत्व और बढ़ गया है।
- समारोह में देश भर से सैकड़ों संतों ने भाग लिया और मंदिर परिसर में 72 घंटे तक निरंतर 'ओम' का जाप किया गया।
- सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे जो भारत की सभ्यता की अटूट भावना, समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण एवं उत्सव के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को जाहिर करती है।



एक हजार साल बाद भी सोमनाथ मंदिर पर लहरा रहा है ध्वज

- सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया लेकिन, कुछ वर्षों के भीतर ही सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो गया।
- 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण कर दिया। चौदहवीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ के राजा ने फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कर दी।
- चौदहवीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में मुजफ्फर खान ने सोमनाथ पर फिर हमला किया, वो हमला भी नाकाम रहा।
- पंद्रहवीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर को दूषित करने की कोशिश की। इसी शताब्दी में उसके पोते सुल्तान महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ पर आक्रमण कर मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की। लेकिन महादेव के भक्तों के प्रयासों से मंदिर पुनः जीवंत हो उठा।
- सत्रहवीं-अठारवीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया। उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया, सोमनाथ को फिर मस्जिद बनाने की कोशिश की। अहिल्याबाई होल्कर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया।



जब हम आस्था से जुड़े रहते हैं, जड़ों से जुड़े रहते हैं, पूरे स्वाभिमान के साथ विरासत का संरक्षण करते हैं, विरासत के प्रति सजग रहते हैं तो हमारी सभ्यता की जड़ें भी मजबूत होती हैं। इसीलिए, पिछले एक हजार वर्षों की यात्रा, हमें अगले एक हजार वर्षों के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देती है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

साकार हो रही है। आज एक ओर, सोमनाथ मंदिर का सांस्कृतिक विस्तार, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना, माधवपुर मेले की लोकप्रियता और उसके रंग से विरासत मजबूत हो रही है, गिर शेर के संरक्षण से इस क्षेत्र का प्राकृतिक आकर्षण बढ़ रहा है, तो वहीं प्रभास पाटन क्षेत्र विकास के नए आयाम भी गढ़े जा रहे हैं।

केशोद एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे देश-विदेश से श्रद्धालु सीधे सोमनाथ तक पहुंच सकेंगे। आज का भारत आस्था को स्मरण करने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के जरिए उसे भविष्य के लिए सशक्त भी कर रहा है। ■

आवरण कथा
कृषि व किसान कल्याण



संपन्न किसान उन्नत भारत

आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर भारत का मूल आधार है। किसानों को लागत से डेढ़ गुनी कीमत दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना हो, किसानों की आय दोगुनी करना या फिर 1 फरवरी 2019 को पेश आम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि से आर्थिक रूप से सशक्त-समृद्ध बनाने की पहल, यह वादा नहीं, बीज से बाजार तक सरकार के लिए देश के अन्नदाता किसानों का हित सर्वोच्च संकल्प बन गया है। समग्रता में किसानों को सुदृढ़ बनाने के लिए बुवाई से पहले, बुवाई के दौरान और बुवाई के बाद के सभी चरणों में पहल, नीति और योजनाओं से इन्हें सशक्त किया जा रहा है। विकसित भारत की यात्रा के महत्वपूर्ण आधार बने किसानों के लिए हो चुकी है नए युग की शुरुआत...



**‘सुवर्ण-रौप्य-माणिक्य-वसनैरपि पूरिताः ।
तथापि प्रार्थयन्त्येव किसानान् भक्ततृष्णया ॥’**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संस्कृत सुभाषितम साझा किया, तात्पर्य है कि सोना, चांदी, माणिक और उत्तम वस्त्र होने के बावजूद लोगों को भोजन के लिए किसानों पर निर्भर रहना पड़ता है।

कृषिर्धन्या कृषिर्मध्या जन्तूनां जीवनं कृषिः

यह श्लोक कृषि के महत्व को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है और कृषि ही प्राणियों का जीवन है। यह श्लोक बताता है कि कृषि न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि सभी जीवित प्राणियों के लिए भी आवश्यक है।

जय जवान, जय किसान

किसान राष्ट्र का मौन योद्धा होता है। यानी युद्धभूमि में दिखाई देने वाला सैनिक जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण वह किसान है जो खेतों में पसीना बहाता है और रसद पहुंचाता है। यदि किसान अन्न न उगाए तो सैनिकों का शौर्य भी व्यर्थ हो जाएगा। युद्ध के समय किसान की भूमिका और बढ़ जाती है क्योंकि उसी के द्वारा पहुंचाया गया भोजन सैनिकों का मनोबल, शक्ति, धैर्य बनाए रखता है।

**आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख,
मंदिरों, राजप्रासादों में, तहखानों में?
देवता कहीं सड़कों पर गिड़ती तोड़ रहे,
देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में।**

—रामधारी सिंह दिनकर

सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था, **‘इस धरती पर अगर किसी को सीना तानकर चलने का हक है तो वह धन-धान्य पैदा करने वाले किसान को है।’**

यह सुभाषितम, श्लोक, कविता, उद्धरण बताता है कि कृषि और किसान एक राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि राष्ट्र की रीढ़ हैं जो शांति और युद्ध दोनों का आधार है। देश केवल तलवार से नहीं, हल से भी बचता है, जो खेत में अन्न उगाता है, वही युद्ध जीतने की नींव रखता है। सैनिक और किसान दोनों राष्ट्र के रक्षक हैं। यही सोच नए भारत के कृषि व किसान कल्याण का आधार है। विकसित भारत के निर्माण में देश के अन्नदाता किसानों की बड़ी भूमिका है। इसलिए केंद्र सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दिन-रात काम कर रही है। आज बीज से बाजार तक केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खेती और किसानों सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। भारत का किसान अब भारत की विकास यात्रा का सहभागी बन चुका है।

विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। इसके लिए जरूरी विषयों पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है। जैसे किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले? कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो? देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे फसलें पैदा हों? कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही दुनिया की जरूरत

आर्थिक सशक्तीकरण

पीएम किसान सम्मान निधि

4.09

लाख करोड़ रुपये

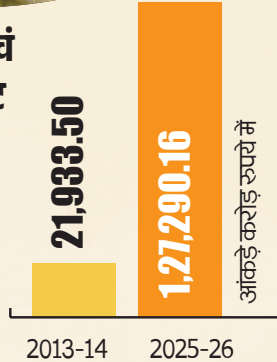
से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों को 21 किस्तों में दी जा चुकी है।

- 9.34 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को पीएम किसान योजना का लाभ मिला है जिनका ई-केवाईसी भी पूरा किया जा चुका है। अभी देश में 42.85 लाख किसानों का ई-केवाईसी होना बाकी है।
- पीएम किसान के तहत कृषि योग्य भूमि वाले किसानों के लिए एक आय सहायता योजना है। इसके तहत तीन समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान का शोध निष्कर्ष बताता है पीएम किसान ने किसानों की ऋण संबंधी बाधाओं को कम किया है। किसानों की जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार किया है। कृषि आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस राशि का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा और विवाह जैसे अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भी किया गया है।

85 फीसदी से अधिक लाभार्थी किसानों ने नीति आयोग के अध्ययन में बताया है कि कृषि आय में वृद्धि, फसल खराब होने या आपात चिकित्सा के दौरान अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में पीएम किसान की वजह से कमी आई है।

480 फीसदी बढ़ा कृषि एवं किसान कल्याण का बजट



प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना

- 24,000 करोड़ रुपये के खर्च वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का 11 अक्टूबर, 2025 को पीएम मोदी ने शुभारंभ किया।
- 100 जिलों का चयन योजना के लिए तीन पैरामीटर पर। पहला-खेत से कितनी पैदावार होती है, दूसरा-एक खेत में कितनी बार खेती होती है, तीसरा- किसान को लोन या निवेश में कितनी सुविधा है।
- योजना देश के आकांक्षी जिलों में कृषि उत्थान के लिए 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाओं को समन्वित करते हुए लॉन्च की गई है।
- उद्देश्य : कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और चयनित 100 जिलों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है।

भी पूरी करे? दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने? कैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटें? कैसे कम पानी में अधिक अनाज उत्पादन करें? कैसे भूमि को खतरनाक रसायनों से बचाया जाए? कैसे खेती को आधुनिक बनाया जाए? विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचे? ऐसे अनेक विषयों पर बीते 11 वर्ष में केंद्र सरकार ने काम किया है, ताकि भारत की खेती को विकसित भारत का प्रमुख आधार बनाया जा सके।

किसान सशक्तीकरण का नया युग

भारत में लगभग 68 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी आजीविका या तो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है अथवा कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों से संबद्ध है। इस तरह देखा जाए तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश का लगभग 44 फीसदी श्रमबल खेती और इससे जुड़े व्यवसायों से रोजगार प्राप्त करता है। खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानों को सरकार का

उपज को सही बाजार और किसानों को सही दाम

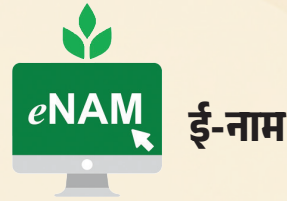
पीएम कृषि उड़ान योजना

- गुवाहाटी से 'किंग चिलीज, बर्मी अंगूर और असमिया नींबू', त्रिपुरा से 'कटहल' और बिहार के कई जिलों से 'लीची' अब देश और विदेश के दूसरे हिस्से में आसानी से पहुंच रही है। यह कृषि उड़ान योजना से संभव हुआ है जिसकी शुरुआत 2021 में की गई।
- 35 हवाई अड्डों पर कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध है। योजना में 58 हवाई अड्डे सूचीबद्ध हैं। यह योजना मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र के 25 हवाई अड्डों पर केंद्रित है।



कृषि निर्यात

- सरकार कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं के निर्यात और वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
- वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं का रिकॉर्ड 51.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया।

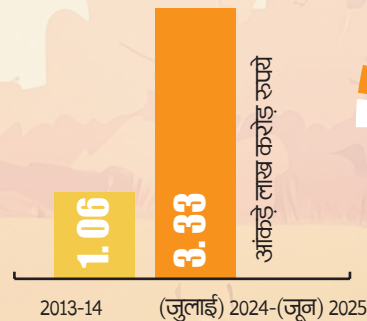


- किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) का शुभारंभ हुआ। 4.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कृषि उपज का कारोबार ई-नाम के माध्यम से किया गया।
- 1.79 करोड़ से ज्यादा किसान, 3.90 लाख व्यापारी और कमीशन एजेंट के अलावा 4, 642 किसान उत्पादक संगठन इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। 27 राज्यों की 1,522 मंडियां इससे जुड़ी हैं। आंकड़े 31 दिसंबर 2025 तक।

एमएसपी में वृद्धि

- सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारत औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ आदेश में शामिल सभी अधिसूचित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। बीते एक दशक की इसी अवधि में सरकारी अनाज खरीदी 761. 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1,175 लाख मीट्रिक टन हो गई।

एमएसपी के तहत किसानों का भुगतान करीब तीन गुना बढ़ा



भारतीय कृषि और ग्रामीण समृद्धि में बदलाव लाने में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। चाहे फसल की खेती हो, पशुपालन हो या प्राकृतिक खेती, महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रमुख नेता के रूप में उभर रही हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सहयोग मिलता रहे लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के तत्काल बाद कृषि क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना जरूरी था। कृषि को लेकर स्पष्ट विजन का अभाव दिखता था। खेती से जुड़े अलग-अलग सरकारी विभाग भी अपने-अपने तरीके से काम करते थे। इस वजह से भारत की कृषि व्यवस्था को गति नहीं मिल पा रही थी।

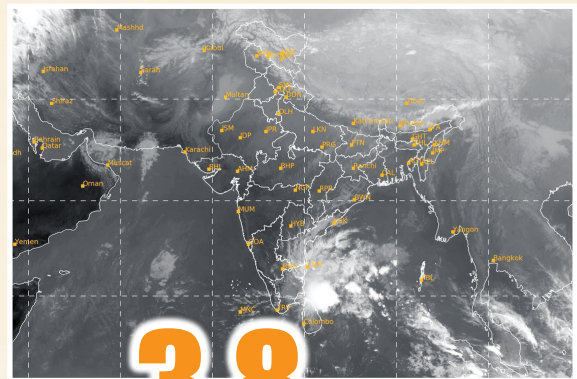
21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए अपनी कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना आवश्यक था। ऐसे में कृषि क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से सुधार की पहल 2014 में प्रधानमंत्री

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल रही मजबूती

कृषि विज्ञान केंद्रों का बढ़ा नेटवर्क

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित ये केंद्र किसानों के प्रशिक्षण में सबसे आगे हैं।
- 2021-22 और 2023-24 के बीच, केवीके ने 58.02 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया जबकि 2024-25 में भी 19 लाख से अधिक किसान प्रशिक्षित।
- कृषि विज्ञान केंद्रों के पाठ्यक्रमों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्नत कृषि विज्ञान, पशुधन देखभाल, मृदा स्वास्थ्य, कटाई के बाद की तकनीक आदि शामिल हैं।

एआई आधारित पूर्वानुमान



3.8 करोड़

किसानों को एम-किसान पोर्टल के माध्यम से इस अनूठी पहल के तहत पिछले साल एआई-आधारित मानसून पूर्वानुमान 5 क्षेत्रीय भाषा में भेजे गए।

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

1 लाख करोड़ रुपये

के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए। इस योजना में 2 करोड़ रुपये तक 3 फीसदी ब्याज पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें क्रेडिट गारंटी कवरेज भी दी जाती है।

- 1,34,372 परियोजनाओं के लिए 75,140 करोड़ रुपये 30 अक्टूबर, 2025 तक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत स्वीकृत किए जा चुके हैं। इससे कृषि क्षेत्र में 1.20 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा।

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मई, 2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को स्वीकृति दी। पायलट परियोजना के अंतर्गत 11 राज्यों के 11 पीएसीएस में गोदामों का निर्माण पूरा।

500

से अधिक पैक्स की पहचान योजना के लिए की गई। 108 में निर्माण कार्य शुरू जिनमें 24 का निर्माण पूरा हो चुका है। दिसंबर 2026 तक सभी निर्माण पूरा करने का लक्ष्य।



नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरंभ हुई। किसानों का सशक्तीकरण और उनकी आय में वृद्धि करना पहली प्राथमिकता बनी। बीते 11 वर्ष में ऐतिहासिक सुधारों की एक ऐसी नींव रखी गई है जिस पर अमृतकाल में नए भारत की इमारत खड़ी होना प्रारंभ हो गई है, इन्हीं सुधारों में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। 1 फरवरी 2019 का अंतरिम बजट, कृषि क्षेत्र और किसान के सशक्तीकरण के युग में एक नया अध्याय लेकर आया। जब किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और जरूरत के वक्त साहूकारों के चंगुल से बचाने वाली महत्वपूर्ण योजना-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू करने की क्रांतिकारी घोषणा हुई। केंद्र सरकार की नीति-नीयत-निर्णय की त्रिवेणी कैसे काम करती है, इसका उम्दा उदाहरण है यह योजना। जिसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को हुई और पूर्व की तारीख यानी 1 दिसंबर 2018 से ही लागू करते हुए किसानों के बैंक खाते में सीधे 2,000 रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित कर दी गई। यह देश की आजादी के बाद किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना बनी।

सभी किसानों के हित में, बीज से लेकर बाजार तक

किसानों के जीवन को मिला सुरक्षा कवच

किसान क्रेडिट कार्ड

- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का 2019 में विस्तार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए भी किया गया। 2025-26 के बजट में लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।

7.7

करोड़ से अधिक किसान, मधुआरे और डेयरी किसान को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है।

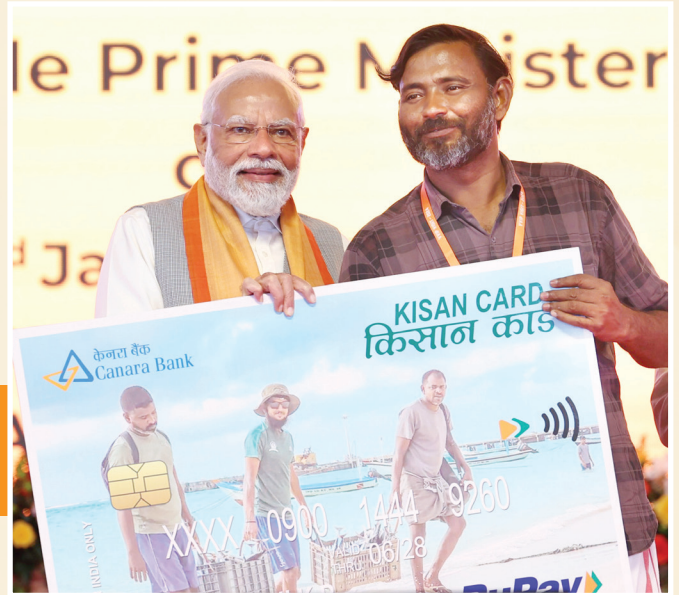
10

लाख करोड़ रुपये

से अधिक के ऋण और 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक ब्याज सब्सिडी किसान क्रेडिट कार्ड लाभार्थियों को 2024-25 में दी गई है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

- 10 हजार से ज्यादा एफपीओ ने पूरे भारत के किसानों को सशक्त बनाया। देशभर में 52 लाख किसान, अक्टूबर, 2025 तक एफपीओ से जुड़ चुके हैं।
- 1,100 एफपीओ करोड़पति बनकर 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर दर्ज कर चुके हैं। वित्त वर्ष 2027-28 तक 6,800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।



पीएम मान धन

- प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें 60 वर्ष की आयु पर न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन 3,000 रुपये तय है।
- 24.88 लाख नामांकन योजना में जुलाई, 2025 तक कराए गए हैं।

श्रीअन्न यानी मिलेट्स की मार्केटिंग और विकास

- वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। मई 2025 तक, मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी जो दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि 596 रुपये प्रति क्विंटल है।
- 180.15 लाख टन मिलेट का उत्पादन और 89 हजार टन से अधिक का निर्यात भारत ने 2024-25 में किया। उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे रहा, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान रहा।



अनगिनत सुधार किए गए। इसी का परिणाम है कि बीते 11 वर्षों में, भारत का कृषि निर्यात करीब-करीब दो गुना हो गया। अनाज उत्पादन पहले से करीब-करीब 900 लाख मीट्रिक टन और बढ़ गया, फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। आज दूध उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर वन है, भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मछली उत्पादक है। 11 वर्ष पहले जितना शहद भारत में उत्पादित होता था, आज उसका करीब-करीब दोगुना उत्पादन होता है। छह-सात साल पहले करीब साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का

शहद निर्यात होता था लेकिन हाल ही में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का शहद निर्यात हुआ है।

अंडे का उत्पादन भी बीते 11 वर्षों में दोगुना हो गया है। इस दौरान देश में 6 बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बनाई गई हैं। 25 करोड़ से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को मिले हैं, 100 लाख हेक्टेयर भूमि में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंची है। पीएम फसल बीमा योजना से करीब दो लाख करोड़ रुपये के भुगतान किसानों को मिले हैं। बीते 11 साल में 10 हजार से ज्यादा किसान उत्पाद संघ भी बने हैं।



पारंपरिक एवं प्राकृतिक खेती पर बड़ा फोकस

परंपरागत कृषि विकास मिशन

- परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली पहली बड़ी स्कीम है। जिसकी शुरुआत 2015-16 में की गई।

28.34
लाख

किसान योजना की शुरुआत से 31 अक्टूबर, 2025 तक लाभांशित। योजना के तहत 16.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल कवर और 58,155 क्लस्टर जैविक खेती के बनाए गए।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

- यह मिशन 25 नवंबर 2024 को शुरू। मिशन का लक्ष्य 15,000 समूहों के माध्यम से 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती है। 1 करोड़ किसान होंगे लाभांशित।

14.3
लाख

से अधिक किसान अगस्त, 2025 तक राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से जुड़ चुके हैं।

- 5.45 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक किसान को 2 वर्ष तक (प्रति किसान एक एकड़) प्रतिवर्ष 4,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन

2015-16 में शुरू इस मिशन का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक कृषि को बढ़ावा देना और जैविक उत्पादन क्लस्टर स्थापित करना है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 46,500 रुपये दिए जाते हैं। वर्ष 2024-25 में 2.69 लाख किसान लाभांशित।

राष्ट्रीय बांस मिशन

- राष्ट्रीय बांस मिशन 23 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू एवं कश्मीर) में बांस की खेती, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देता है।
- भारत में बांस के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल (13.96 मिलियन हेक्टेयर) है। बांस विविधता के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे समृद्ध देश है। भारत का बांस और बेंत उद्योग 28,005 करोड़ रुपये का है।

नए भारत का सफर, खुशहाल होता किसान

आजादी के शताब्दी वर्ष के दृढ़ संकल्प के साथ भारत का किसान यानी अन्नदाता भी देश की विकास यात्रा का सहभागी बन चुका है। 1947 में जब आजादी मिली तब देश के सामने सबसे बड़े संकटों में से एक था कि कैसे पूरे देश का पेट भरा जाए और इतना खाद्यान्न कहां से लाएं कि लोगों को भूखे पेट न सोना पड़े। लेकिन हरित क्रांति के सहारे देश के अन्नदाताओं ने यह संभव कर दिखाया। बावजूद इसके, आजादी के 7 दशक बाद भी किसानों की समस्याएं कम नहीं हुईं। अब कृषि को उद्योग की तरह ढांचा देने और किसानों को

बिचौलियों से मुक्त कर अपनी फसल को अपनी मर्जी से बेचने की छूट देने की दिशा में किसानों को कानूनी कवच मिल चुका है, ताकि किसान खुशहाल हों और कृषि आत्मनिर्भर भारत का अहम हिस्सा बने। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2014 से ही किसानों के कल्याण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेने शुरू कर दिए थे।

सरकार की पहल एक राष्ट्र-एक बाजार की सोच के तहत थी, जिसका एलान प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में लाल किले के प्राचीर से किया था। यह एक ऐसा सुधार था जिसका आजादी के बाद से ही किसानों को इंतजार था। केंद्र सरकार ने इस एलान के पहले से ही

फसल संरक्षण से समृद्धि की राह

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

पीएमएफबीवाई की शुरुआत 18 फरवरी, 2016 को की गई। अब जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान और धान की फसल में जलभराव दोनों पीएमएफबीवाई में शामिल। खरीफ सीजन 2026 से पूरे देश में लागू की जाएंगी।

92.92 करोड़ किसान आवेदकों की 55.48 करोड़ हेक्टेयर फसल का बीमा, योजना की शुरुआत से 8 जनवरी, 2026 तक किया गया। आवेदकों में 50% से अधिक ओबीसी, एससी और एसटी किसान।

1,91,620 करोड़ रुपये का क्लेम किसानों को मिला। किसानों ने 39,446 करोड़ रुपये के प्रीमियम का भुगतान किया था।

उर्वरक

किसानों को 1,633 रु. वाली यूरिया की बोरी सरकार 266 रु. में और डीएपी की 50 किलो की 3,100 रु. वाली बोरी 1,350 रु. में उपलब्ध कराती है। शेष राशि सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करती है।

14.6 लाख करोड़ रुपये उर्वरक सब्सिडी पर सरकार ने खर्च किए।

525 लाख टन के करीब यूरिया का उत्पादन वर्ष 2025 में हुआ।

चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया था। 14 अप्रैल 2016 को ही एक देश-एक बाजार की दिशा में ई-नाम प्लेटफॉर्म की व्यवस्था साकार रूप ले चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच समूचे राष्ट्र के किसानों का संतुलित और समुचित विकास करना है क्योंकि अभी तक मुट्ठी भर समृद्ध किसानों को ही इसका लाभ मिल रहा था और लगभग 86 फीसदी छोटे और सीमांत किसान इससे वंचित थे। लेकिन, बीते 11 साल में कृषि क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके यानी बुवाई से पहले, बुवाई के दौरान और बुवाई के बाद की योजनाओं पर जिस तरह से काम हुआ है उससे देश के किसान सबल और

मृदा स्वास्थ्य

सरकार सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना के माध्यम से उर्वरक के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। कम से कम तीन वर्ष में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड खेत का जारी किया जाता है।

25.61 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की 2014-15 में शुरुआत से 9 दिसंबर, 2025 तक वितरित किए गए। 40 आकांक्षी जिलों में 290 लाख हेक्टेयर भूमि पर मृदा मानचित्रण का कार्य पूरा हो चुका है।

फसल विविधीकरण कार्यक्रम

योजना का उद्देश्य किसानों को धान जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों को दलहन, तिलहन और मोटे अनाज जैसे विकल्पों की ओर परिवर्तित करना है।

- 184 नवीन प्रजातियां 25 फसलों की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी के प्रकार और खेती की पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए विकसित की हैं जो फसल विविधीकरण को गति देगी।



सशक्त हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। अगर उदाहरणों में देखें तो सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन, एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। किसान और सरकार की इसी साझेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं।

किसानों को सबसे बड़ा सम्मान

किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की जो अब तक के इतिहास में किसानों के लिए नहीं हुई



जीएसटी सुधार से कृषि को मिला लाभ

कृषि क्षेत्र में जीएसटी बदलाव किसान अनुकूल, ग्रामीण कल्याण और स्थिरता की दिशा में उठाया गया एक कदम है जिससे किसानों की लागत में कटौती होगी। साथ में सहकारी समिति एवं किसान उत्पादक संगठनों को भी लाभ मिलेगा।

- 5 फीसदी किया गया 1,800 सीसी से नीचे के ट्रैक्टर पर लगने वाले 12% के जीएसटी को। वहीं ट्रैक्टर कलपुर्जो पर जीएसटी भी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की गई।
- 18 फीसदी की गई जीएसटी कॉमर्शियल माल वाहनों पर 28 फीसदी से घटाकर।
- 5 फीसदी की गई तैयार और संरक्षित सब्जी, फल और नट्स पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर। निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, कृषि निर्यात केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी।
- 5 फीसदी किया गया उर्वरक इनपुट यानी अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड पर जीएसटी, 18 फीसदी से घटाकर। इससे उर्वरक उत्पादन लागत में कमी आएगी जिससे किफायती उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

पानी पहुंचा खेत तक खर्च घटा जेब पर

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- 96.97 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 'प्रति बूंद अधिक फसल' के तहत लाभांशित। प्रति बूंद अधिक फसल योजना 2015-16 से लागू है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाती है।
- 63 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं मंजूर, 2 करोड़ से अधिक किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा से सशक्त बनाया गया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-2026 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप-योजना के रूप में कमना क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी।

पीएम कुसुम योजना

- मार्च 2019 में शुरू पीएम-कुसुम योजना का जनवरी 2024 में विस्तार किया गया।

34,800

मेगावाट सौर क्षमता को जोड़ना योजना का लक्ष्य, 34,422 करोड़ रु. की केंद्रीय वित्तीय सहायता मार्च 2026 तक दी जाएगी।



थी। किसानों को सम्मान निधि के तहत 6 हजार रुपये सालाना तीन किस्तों में देने की शुरुआत कर सरकार ने किसानों को कर्ज माफी की बजाय सशक्त करने की पहल की, ताकि उसे कर्ज नहीं लेना पड़े। वर्ष 2008 में किसानों के लिए 72 हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी की योजना का एलान किया गया था, जो बाद में महज 52 हजार करोड़ रुपये की ही निकली। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2025 तक 21 किस्तों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक किसानों को सीधे बैंक खाते में पहुंचा दिए गए हैं। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपये तो कोरोना के मुश्किल समय में ही छोटे किसानों



आज गांवों में नमो ड्रोन दीदियां... खाद और कीटनाशक छिड़काव के आधुनिक तरीकों का नेतृत्व कर रही हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पशुपालन, मछली पालन और बागवानी में भी सरकार का साथ

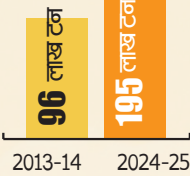
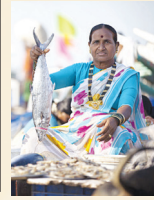
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने मछुआरों को रिकॉर्ड पैदावार, बढ़ते निर्यात और समावेशी एवं सतत विकास के साथ सशक्त बनाया जिसकी 10 सितंबर, 2020 को शुरुआत की गई थी। अब भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बना।

58 लाख

आजीविका सृजन और 99,018 महिलाओं का योजना से हुआ सशक्तीकरण।

11 वर्षों में दोगुना से अधिक हुआ मछली उत्पादन



गोकुल मिशन

विश्व की 14% गाय और 57% भैंस के साथ पशु आबादी के मामले में भारत पहले नंबर पर है। 16 दिसंबर, 2014 को देसी गोजातीय यानी बोवाइल नस्लों के विकास और संरक्षण, दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई।

- 1.28 करोड़ सेक्स सॉर्टेड सीमेन खुराक का उत्पादन; स्वदेशी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लागत 800 रुपये से घटाकर 250 रुपये प्रति खुराक की गई।

14.56 करोड़

पशुओं का गर्भाधान मिशन के कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में कराया गया। 9.36 करोड़ पशु योजना में शामिल। 5.62 करोड़ से अधिक किसान इसके लाभार्थी।



कृषि वानिकी



फसल और फसल प्रणालियों के साथ-साथ खेत पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत कृषि वानिकी पर उप-मिशन (एसएमएएफ) कार्यान्वित किया गया।

3.93 करोड़

हेक्टेयर कृषि वानिकी क्षेत्र भारत का है। भारत और इंडोनेशिया का कुल कृषि वानिकी क्षेत्र एशिया में कृषि वानिकी क्षेत्र का करीब-करीब शत प्रतिशत है। वैश्विक स्तर पर योगदान लगभग 70% है।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन

आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के तौर पर राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन शुरू किया गया ताकि 'मीठी क्रांति' का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

- भारत जुलाई, 2025 में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहद निर्यातक बना, वर्ष 2020 में नौवें स्थान पर था।

1.07 लाख

मीट्रिक टन प्राकृतिक शहद का उत्पादन 2023-2024 में भारत ने किया।



तक पहुंचे हैं। यही नहीं, कोरोना काल में ही 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से अधिकतर छोटे किसान हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों ने हजारों करोड़ रुपये का ऋण भी लिया है। कल्पना कीजिए, अगर यह मदद छोटे किसानों को न मिलती तो, 100 वर्ष की इस सबसे बड़ी आपदा में उनकी क्या स्थिति होती? उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए कहां-कहां नहीं भटकना पड़ता? अब किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ा जा चुका है। अगर ताजा आंकड़ों को देखें तो केसीसी से वर्ष 2025 में किसानों को 10 लाख करोड़

रुपये से ज्यादा की मदद मिली। आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप-10 देशों में पहुंचा है।

ताकि धन-धान्य से परिपूर्ण हो राष्ट्र

आज देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि वो कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हर क्षेत्र में बेहतर करने के प्रयास हो रहे हैं। इसी सोच का परिणाम है वर्ष 2025 में किसानों की मदद के लिए 35 हजार करोड़ रुपये की दो नई योजनाओं की शुरुआत जिनमें शामिल है- पीएम धन-

कृषि और किसान को मिला तकनीक का साथ

केंद्र सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत की है। इसमें डिजिटल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरकता और प्रोफाइल मानचित्र एवं आईटी पहल शामिल हैं।

15,000

ड्रोन खरीदने की योजना केंद्र सरकार ने मंजूर की है जिसमें 1,094 ड्रोन वितरित किए गए हैं और ड्रोन दीदी को प्रशिक्षण भी दिया गया है।



75%

राशि का अनुदान किसान उत्पादक संगठनों को किसान ड्रोन की खरीद पर दिया जाता है। किसानों को किराये पर ड्रोन उपलब्ध कराने वाली सहकारी समिति, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों को भी ड्रोन की खरीद पर 40% की दर से अधिकतम 4 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

7.68

 करोड़

किसान आईडी 4 दिसंबर 2025 तक बनाए जा चुके हैं 14 राज्यों में। इन राज्यों में पीएम किसान योजना में पंजीकरण के लिए किसान आईडी अनिवार्य किया गया है।

2,096

कृषि स्टार्टअप को 2019-20 से 2025-26 तक नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सरकार ने तकनीकी और वित्तीय सहायता दी है।

- 2.76 करोड़ संपत्ति कार्ड स्वामित्व योजना के तहत 1.82 लाख गांवों में तैयार किए जा चुके हैं। 3.28 लाख गांव में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। मार्च, 2026 तक 3.44 लाख गांव को कवर करने का लक्ष्य है।

- कृषि मशीनीकरण : देश में विभिन्न फसलों और उनके कृषि संचालन में कृषि मशीनीकरण का औसत स्तर अलग-अलग है। बीज की क्यारी तैयार करने के लिए 70%, बुवाई-रोपण में 40%, निराई में 33% और कटाई और थ्रेसिंग के लिए 34% है। परिणामस्वरूप कुल औसत मशीनीकरण 45% है।



धान्य कृषि योजना। इस योजना की प्रेरणा बनी है, आंकाक्षी जिला योजना की सफलता। केंद्र सरकार ने जिस तरह से 112 पिछड़े जिलों पर फोकस किया, उसी तरह से अब ऐसे क्षेत्रों की पहचान कृषि के विकास के लिहाज से की गई है। पीएम धन-धान्य कृषि योजना का डिजाइन ऐसा है कि हर जिले की अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी योजना में बदलाव लाया जा सकता है। दूसरा है- दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन केवल दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खेती के अलावा भी किसानों के लिए कई रास्ते खोले हैं और उनमें मदद कर रही है। पशुपालन से लेकर मधुमक्खी पालन और मछली पालन से लेकर आर्गेनिक खेती तक, केंद्र सरकार ने तमाम मोर्चों पर किसानों को नई राह दिखाई है। किसान रेल की शुरुआत हो या फिर राष्ट्रीय बांस मिशन, किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम अभी भी जारी है। अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे जहां, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे। यानी एक

तेल और दलहन में आत्मनिर्भरता की तरफ बड़े कदम

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल मिशन

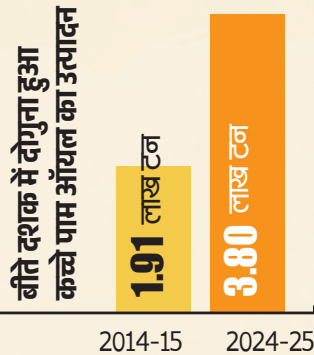
मिशन को 2021 में मंजूरी मिली, 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय खर्च निर्धारित किया गया।

6.5
लाख

हेक्टेयर क्षेत्र को पाम ऑयल की खेती 2025-26 तक मिशन में लाने का लक्ष्य, कच्चे पाम ऑयल (सीपीओ) का उत्पादन 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य।

1.89
लाख

हेक्टेयर क्षेत्र को मिशन के तहत मार्च, 2025 तक कवर किया गया। देश में पाम ऑयल का कवरेज 5.56 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा।



राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन

- खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन को 2024 में मंजूरी दी गई।
- मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक क्षेत्र कवरेज को 29 मिलियन हेक्टेयर (2022-23) से बढ़ाकर 33 मिलियन हेक्टेयर पहुंचाना है।
- 25.45 मिलियन टन 2030-31 तक खाद्य तेल का उत्पादन पहुंचाना है मिशन का लक्ष्य जो हमारी अनुमानित घरेलू आवश्यकता का लगभग 72 प्रतिशत पूरा करेगा।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

- प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर, 2025 को 11,440 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31) का शुभारंभ किया।
- किसानों के बीच कुल 88 लाख निःशुल्क बीज किट और 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये जायेंगे। करीब दो करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

350
लाख टन

तक दाल का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही दलहन कृषि क्षेत्र का विस्तार 2030-31 तक 310 लाख हेक्टेयर भूमि तक करने का लक्ष्य। योजना में चार वर्षों तक एमएसपी पर तुअर, उड़द और मसूर की शत-प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करना है।



तरह से हम कह सकते हैं- जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इन तीनों की ताकत जब एकजुट होकर काम करेगी, तब देश के किसानों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने तय हैं।

डेढ़ गुनी एमएसपी: उपज का सही दाम

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और उत्पादन की सही कीमत देने के तीन महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। सरकार का एक ही ध्येय और फॉर्मूला है और वह है किसानों का कल्याण। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में तय किया

“
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन...सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। वहीं, पीएम धन धान्य कृषि योजना की एक बड़ी भूमिका है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी किसान

किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी हैं, उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सभी क्षेत्रों में युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित पोंगल समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के युवा नेचुरल फार्मिंग में बेहतरीन काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने खेती से जुड़े तमिल के युवाओं से आग्रह किया कि वे सस्टेनेबल खेती में क्रांति लाने के इस अभियान का और विस्तार करें। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, जब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे।

कि लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय की जाएगी, वहीं किसानों से तुअर, मसूर व उड़द 100% खरीदी तय की गई। जबकि पहले कहा जाता था कि लागत पर सीधे 50% बढ़ोतरी निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह मानते हुए कुल लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी पर फसल खरीदी हो रही है और कई फसलों पर तो 50% से ज्यादा दाम भी दिए जा रहे हैं। कई बार राज्य सरकार खरीदी में ढिलाई बरतती है, ऐसे में केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि तुअर, मसूर, उड़द राज्य सरकार अगर कम खरीदेगी या नहीं खरीदेगी तो नेफेड जैसी एजेंसी के माध्यम से सीधे भी केंद्र खरीदेगा, ताकि किसानों को उचित कीमत मिल सके।

2004 से 2014 के बीच खरीफ फसल की एमएसपी पर केवल 46 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 81 करोड़ 86 लाख मीट्रिक टन खरीद की है। इसी तरह पहले रबी की फसल 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी, वहीं वर्तमान में केंद्र सरकार ने 35 करोड़ 40 लाख मीट्रिक टन खरीद की है। यही नहीं अलग-अलग दलहन और तिलहन की खरीदी भी की।

पहले तिलहन 47 लाख 75 हजार मीट्रिक टन खरीदी जाती थी, वहीं वर्तमान सरकार ने 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन की खरीद की है। दलहन 6 लाख मीट्रिक टन 10 साल में खरीदी, वहीं अब 1 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। पूर्व के 10 साल में एमएसपी पर 7 लाख 41 हजार करोड़ रुपये की फसलें खरीदी गईं, वहीं अब 24 लाख 49 हजार करोड़ रुपये की खरीद की गई है।

जीएसटी 2.0 और किसान

2025 की दीपावली से ठीक पहले जीएसटी 2.0 ने हर किसान, हर पशुपालक का खर्च कम करते हुए लाभ पहुंचाया है। ट्रैक्टर और भी सस्ते हुए हैं। नए सुधार के बाद ट्रैक्टर की खरीद में सीधे करीब 40 हजार रुपये की बचत हो रही है। किसानों के उपयोग की बाकी मशीनों पर भी जीएसटी बहुत कम किया गया है। जैसे धान रोपने की मशीन, उस पर अब पंद्रह हजार रुपये की बचत हो रही है। इसी तरह पावर टिलर पर दस हजार रुपये की बचत हुई है, श्रेशर पर 25 हजार रुपये तक की बचत तो टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई से जुड़े उपकरण, कटाई मशीन, सभी पर जीएसटी में भारी कमी की गई है।

2047 के भारत की सुनहरी तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभों की चर्चा की थी। इन चार स्तंभों में किसान एक मजबूत स्तंभ हैं। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। केंद्र सरकार की प्राथमिकता बजट में भी दिखती है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में 1,27,290.16 करोड़ रुपये किया गया यानी छह गुणा बढ़ोतरी हुई है। इस बड़े हुए बजट का सबसे अधिक फायदा छोटे किसानों को हुआ है। इसका एक उदाहरण है खाद पर सब्सिडी। अगर 2004-2014 की बात करें तो कुल खाद सब्सिडी 5 लाख करोड़ रुपये की थी लेकिन 2014-2024 की बात करें तो यह 13 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है।

निश्चित रूप से कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण, किसानों का कल्याण ही वर्तमान केंद्र सरकार का सर्वोच्च संकल्प है। बीते 11 वर्ष में कृषि क्षेत्र व



हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही यह पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग-अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

किसान कल्याण के लिए समग्रता में हुई पहल यह सिद्ध करती है कि जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है तभी इस तरह की योजनाएं मुमकिन होती हैं। केंद्र सरकार एक नए दृष्टिकोण के साथ बीज से बाजार तक, खेत से खलिहान तक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है, जो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का आधारस्तंभ बन रहा है। ■



नीति से नवाचार तक युवाओं की निर्णायक भागीदारी

भारत की युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। ऊर्जा, नवाचार और नेतृत्व क्षमता से भरपूर युवा आज न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्र की दिशा भी तय कर रहे हैं। “विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2026” युवा विचारों के मंथन, नेतृत्व के उदय और विकसित भारत के निर्माण का सशक्त मंच है, जहां वह देश के विकास एजेंडे का हिस्सा बनते हैं। यही वजह है कि इस संवाद के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा कि आपके सामर्थ्य, टैलेंट, एनर्जी से खुद भी पाता हूं एनर्जी...

वर्ष 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, यह यात्रा भारत के लिए ही नहीं बल्कि युवाओं के जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए, हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और उन्हीं की प्रेरणा से भारत ने इस दिन को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए चुना है। बहुत ही कम समय में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि यहां से देश के विकास की दशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है। करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, 50 लाख से अधिक नौजवानों की रजिस्ट्रेशन, 30 लाख से अधिक युवाओं का विकसित भारत चैलेंज में हिस्सा लेना, देश के विकास

के लिए अपने विचार शेयर करना यह अपने आप में अभूतपूर्व है।

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2026 के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक निश्चित विषय एवं लक्ष्य को लेकर लाखों लोगों का मंथन होना, इससे बड़ी थिंकिंग क्या हो सकती है? सम्मेलन में महिला के नेतृत्व में विकास और लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जैसे विषयों पर युवाओं ने अपने विचार रखे, इससे पीएम मोदी बेहद प्रभावित हुए। सम्मेलन में स्टार्टअप पर दिए गए प्रेजेंटेशन के संबंध में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में 50-60 साल पहले स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ, धीरे-धीरे वो मेगा-कॉर्पोरेशन्स के युग में बदल गया लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान भारत में स्टार्टअप के बारे में बहुत कम चर्चा



विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2026 में हुई मुख्य बातें...

- डिजिटल इंडिया ने भारत में क्रिएटर्स की एक नई कम्युनिटी खड़ी की है। भारत आज 'ऑरेंज इकोनॉमी' यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का विकास होते देख रहा है।
- भारत मीडिया, फिल्म, गेमिंग, म्यूजिक, डिजिटल कंटेंट, वीआर-एक्सआर जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बन रहा है।
- वर्ल्ड ऑडियो-विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेक्स युवा क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्च-पैड बन गई है।
- 10 साल बाद, मैकाले के दुस्साहस को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि 200 साल पहले जो पाप हुआ उसे धोने के लिए हमारे पास 10 साल बचे हैं।
- स्वामी विवेकानंद का जीवन सिखाता है कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर हमें अपनी विरासत और अपने आइडियाज को हमेशा आगे रखना है।
- देश के युवा रामायण और महाभारत की प्रेरक कहानियों को भी गेमिंग वर्ल्ड का हिस्सा बना सकते हैं।
- देश ने नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स का जो सिलसिला शुरू किया है, वो रिफॉर्म अब एक्सप्रेस बन चुका है और इसके केंद्र में युवा शक्ति ही है।



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

हनुमान जी चला सकते हैं पूरी दुनिया की गेमिंग

पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है। देश अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर भी गेमिंग की दुनिया में जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। इससे देश का कल्चर भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, आधुनिक रूप में हो जाएगा और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होगा। देश में कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो गेमिंग की दुनिया में बहुत बढ़िया तरीके से भारत की बातें कह रहे हैं और बच्चों को भी खेलते-खेलते भारत को समझना सरल हो रहा है।

होती थी। अब भारत में हर क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्टार्टअप पर काम हो रहा है। देश में युवाओं के सामर्थ्य को देखते हुए स्टार्टअप रिवोल्यूशन, बिजनेस को आसान बनाने के लिए सुधार, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए कई पहल की गई हैं। 5-6 साल पहले तक स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ इसरो पर थी। सरकार ने स्पेस को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए ओपन किया, इससे जुड़ी व्यवस्था बनाई, संस्थाएं तैयार कीं और आज स्पेस सेक्टर में 300 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर भी पहले सरकारी कंपनियों पर ही निर्भर था। सरकार ने इसको भी बदला, भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में स्टार्टअप के लिए दरवाजे खोले गए। इसका बहुत बड़ा फायदा युवाओं को मिला। आज भारत में 1,000 से अधिक डिफेंस स्टार्टअप काम कर रहे हैं। आज एक युवा ड्रोन बना रहा है, तो दूसरा युवा एंटी-ड्रोन सिस्टम बना रहा है, कोई AI कैमरा बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। ■

भारत को लेकर वैश्विक संस्थाएं 'बुल्लिश' निवेश का यही समय है, सही समय है



भारत को लेकर आज वैश्विक विशेषज्ञ और संस्थाएं, 'बुल्लिश' यानी सकारात्मक हैं। आईएमएफ भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताता है तो एस एंड पी ने 18 वर्ष बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड की है। फिट्च रेटिंग्स भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और फिस्कल क्रेडिबिलिटी की प्रशंसा करती हैं। इन्हीं पहलुओं का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में 11 जनवरी को अपना भरोसा दोहराया...इन संभावनाओं का लाभ उठाने का यही समय है, सही समय है...

आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है। हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बड़ी भूमिका है। भारत की ग्रोथ से जुड़ी फैक्ट शीट... रिफॉर्म-परफॉर्म-ट्रांसफॉर्म की सक्सेस स्टोरी है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारत पर दुनिया का भरोसा इसलिए है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत में हम एक अभूतपूर्व निश्चितता का दौर देख रहे हैं। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में कंटीन्यूटी है। परचेजिंग पावर बढ़ रही है। इन फैक्टर ने भारत को असीम संभावनाओं का देश बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह सम्मेलन भी संदेश दे रहा है- सौराष्ट्र-कच्छ में निवेश का- यही समय है, सही समय है। भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। इस यात्रा में 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' एक बड़ी भूमिका निभा रही है। पीएम मोदी ने निवेशकों को यह विश्वास दिलाया कि रिफॉर्म एक्सप्रेस, अब रुकने

वाली नहीं है। भारत की रिफॉर्म जर्नी, संस्थागत ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ चुकी है। आपके इन्वेस्टमेंट की पाई-पाई यहां शानदार रिटर्न देकर जाएगी।

राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। सम्मेलन के दौरान 14 ग्रीनफील्ड स्मार्ट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एस्टेट्स विकसित करने की घोषणा की तो वहीं जीआईडीसी के मेडिकल डिवाइस पार्क का भी उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में जापान, दक्षिण कोरिया, रवांडा और यूक्रेन ने साझेदार देशों के रूप में अपनी भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने सम्मेलन में कहा कि वैश्विक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ



भारत के रिफॉर्म एक्सप्रेस का हो रहा है सकारात्मक प्रभाव

- रिफॉर्म एक्सप्रेस का अर्थ हर क्षेत्र में नेक्स्ट-जेनरेशन सुधारों को लागू करना है। जीएसटी सुधारों का सकारात्मक प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ा है, विशेष रूप से हमारे एमएसएमई को इससे बहुत लाभ हुआ है।
- भारत ने बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देकर एक बड़ा सुधार किया है, जिससे देश के हर नागरिक को यूनिवर्सल इश्योरेंस कवरेज प्रदान करने के अभियान में तेजी आएगी।
- लगभग छह दशकों के बाद आयकर कानून का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे करोड़ों करदाताओं को बड़ी राहत और सुविधा मिली है।
- ऐतिहासिक श्रम सुधारों से अब वेतन, सामाजिक सुरक्षा और उद्योग को एक एकीकृत ढांचे के भीतर लाया गया है। इन सुधारों से श्रमिकों के कल्याण और उद्योगों की प्रगति, दोनों के बीच एक बेहतर संतुलन स्थापित हुआ है।
- न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म किए हैं। पिछले संसद के सत्र में शांति एक्ट के जरिए, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है। ये निवेशकों के लिए बहुत बड़ा अवसर है।



बीते एक दशक में टॉप देशों में शामिल हुआ भारत

- भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
- भारत पहले दस में से नौ मोबाइल फोन आयात करता था, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश।
- भारत यूपीआई में वैश्विक स्तर पर नंबर वन रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है।
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम।
- सोलर पावर जनरेशन में टॉप तीन देशों में शामिल है।
- भारत तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है।
- दुनिया के टॉप तीन मेट्रो नेटवर्क वाले देशों में भारत भी एक।
- भारत दूध और जेनरिक मेडिसिन उत्पादन में पहले स्थान पर है।
- दुनिया में भारत सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज-2 के सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर तक के शेष हिस्से का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि अहमदाबाद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता विभिन्न विकास कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस सेक्शन से अहमदाबाद और गांधीनगर के लोगों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। गुजरात इस मोर्चे पर पूरी निश्चितता प्रदान करता है। यहां शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय इकोसिस्टम मौजूद है। कौशल्य स्किल यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के

विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार कर रही है। देश की पहली नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और गतिशक्ति यूनिवर्सिटी सड़क, रेलवे, हवाई मार्ग, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के लिए कुशल जनशक्ति तैयार कर रही है। ■

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत की सौर क्रांति

भारत प्राकृति से मिलने वाले सौर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल कर हरित भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। समय से पहले 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का आंकड़ा पार करने के बाद 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। परिवार और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की इसी कड़ी में शुरू प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की 13 फरवरी को दूसरी वर्षगांठ है, यह योजना कर रही है भारत की सौर क्रांति का नेतृत्व...

नवीकरणीय ऊर्जा की आत्मनिर्भरता यात्रा में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' एक क्रांतिकारी पहल है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी, 2024 को करते समय अपील की थी... "आइए सौर ऊर्जा की प्रगति को निरंतर बढ़ावा दें। मैं सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करता हूँ कि वे pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन करके 'पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को मजबूत करें। इस योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी अपील का नतीजा है कि 75,021 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ शुरू इस योजना में न सिर्फ 55 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है बल्कि 21 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए भी जा चुके हैं। इसके लिए 8 लाख से अधिक लोगों को 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लोन दिए गए हैं। योजना ने न सिर्फ



**देश में तेजी से बढ़ता
रूफटॉप सोलर सिस्टम**

(आंकड़े 9 जनवरी, 2026 तक)

55,48,468 आवेदन मिले

21,36,142 आरटीएस लगाए जा चुके

26,76,432 परिवार योजना में कवर

7,879 मेगावाट की क्षमता स्थापित

15,153 करोड़ रुपये
सब्सिडी जारी



मॉडल सोलर विलेज

योजना के 'मॉडल सोलर विलेज' घटक के तहत देश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज स्थापित किया जाना है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार ने इसके लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जिसके तरह प्रत्येक चयनित मॉडल सोलर विलेज को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मॉडल गांव बनने की पात्रता के लिए राजस्व गांव होने के साथ उसकी आबादी 5 हजार से अधिक या विशेष श्रेणी के राज्यों में 2 हजार से अधिक होनी चाहिए। गांवों का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि यह मॉडल सफलतापूर्वक सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर हो और देश भर के अन्य गांवों के लिए एक मिसाल बने।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आय, रोजगार, पर्यावरण सुरक्षा का साधन

- **घरेलू बचत और आय सृजन:** घरों को अपने बिजली बिलों पर महत्वपूर्ण बचत का लाभ मिलेगा। अपने रूफटॉप सोलर सिस्टम की बची हुई बिजली को डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय कर सकते हैं क्योंकि 3-किलोवाट सिस्टम औसतन प्रति माह 300 से अधिक यूनिट उत्पन्न कर सकता है।
- **सौर क्षमता का विस्तार:** आवासीय क्षेत्र में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने से 30 गीगावाट सौर क्षमता जुड़ने का अनुमान है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
- **पर्यावरण लाभ:** इन छत सौर प्रणालियों के 25 वर्ष के जीवनकाल में, अनुमानित 1,000 बिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगी, सीओ₂ उत्सर्जन में 720 मिलियन टन की कमी लाएगी।
- **रोजगार सृजन:** योजना से विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, संचालन और रखरखाव के साथ अन्य सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

सब्सिडी कितनी और कैसे मिलेगी

आप राष्ट्रीय पोर्टल <https://pmsuryaghar.gov.in> के माध्यम से रूफटॉप सोलर सिस्टम की सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर यह पता लगा सकते हैं कि आपके लिए उचित सिस्टम आकार क्या रहेगा और उसे लगाने पर कितना लाभ मिलेगा। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उपभोक्ता नंबर व मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फार्म भरकर बिजली वितरण कंपनी की स्वीकृति मिलने पर रजिस्टर डीलर से सोलर सिस्टम लगावाकर इसकी जानकारी के साथ नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा। बिजली कंपनी निरीक्षण करके प्रमाणित करेगा। अंतिम स्टेप में बैंक डिटेल ऑनलाइन जमा करनी होगी जिसके 30 दिन के भीतर सब्सिडी आ जाएगी।

- घरों के लिए प्रथम 2 किलोवाट तक 30 हजार रुपये प्रति किलोवाट पीक और अतिरिक्त एक किलोवाट पीक के लिए 18 हजार रुपये मिलेंगे। व्यक्तिगत परिवार के लिए सब्सिडी 3 किलोवाट तक सीमित है।
- ग्रुप हाउसिंग या आरडब्ल्यूए के लिए 500 किलोवाट पीक की रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता के साथ केंद्रीय वित्तीय सहायता 18 हजार रुपये प्रति किलोवाट पीक है।
- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता 10 फीसदी अधिक है।
- केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 5.75 फीसदी की दर से बिना गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध है।



लाखों घरों में सौर ऊर्जा सुलभ और किफायती बनाई है बल्कि 1 करोड़ सौर ऊर्जा संचालित घरों के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। बिजली की लागत

कम करने के अलावा, यह योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है, जिससे यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। ■

'आत्मनिर्भर भारत' की पटरी पर दौड़ती 'वंदे भारत एक्सप्रेस'

वंदे भारत ट्रेन ने न सिर्फ सफर को तेज और आरामदायक बनाया है बल्कि सुरक्षित भी किया है। वर्तमान में दो नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सहित 166 वंदे भारत ट्रेन देश के प्रमुख शहरों को जोड़ती है। यह इसकी लोकप्रियता का ही नतीजा है कि 15 फरवरी 2019 से अपनी शुरुआत के बाद से अब तक 7.5 करोड़ से अधिक यात्री अत्याधुनिक ट्रेन से यात्रा का ले चुके हैं लाभ...

वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने वाले श्रीधर कुमार बताते हैं कि अब पटना की यात्रा के लिए वंदे भारत को ही प्राथमिकता देता हूँ। यह ट्रेन थकान-मुक्त और बेहद आरामदायक है। तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा-यही वंदे भारत एक्सप्रेस की पहचान है। वहीं इस ट्रेन के एक अन्य यात्री संतोष गुप्ता का कहना है कि यात्रा बेहद आरामदायक रही। सीटों की सुविधा, ट्रेन की रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं ने सफर को शानदार बना दिया है। आज श्रीधर कुमार, संतोष गुप्ता जैसे 7.5 करोड़ से अधिक यात्री हैं जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन से आरामदायक यात्रा पूरी की है। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित, प्रत्येक ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इनमें स्वचालित प्लग वाले दरवाजे, घूमने वाली सीटें और बायो-वैक्यूम शौचालय शामिल हैं। इनमें जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली और पूर्ण सीसीटीवी कवरेज भी है।



मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों की वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। यह वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है, इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। देश की यह पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, मां काली की धरती को, मां कामाख्या की भूमि को जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



हावड़ा और गुवाहाटी के बीच दौड़ी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

राष्ट्र को नव वर्ष के उपहार के रूप में भारतीय रेल की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच 17 जनवरी 2026 को चलाई गई। इस ट्रेन से असम राज्य के कामरूप महानगरपालिका और बोंगाई गांव एवं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, पूर्वी बर्धमान, हुगली और हावड़ा जैसे जिलों को लाभ मिलेगा। यह ट्रेन यात्रियों को किफायती किराए पर हवाई यात्रा जैसा अनुभव प्रदान करेगी।

- हावड़ा-गुवाहाटी (कामाख्या) मार्ग पर यात्रा के समय को लगभग 2.5 घंटे तक कम करके, यह ट्रेन धार्मिक यात्रा और पर्यटन को भी काफी बढ़ावा देगी।
- ट्रेन में 16 कोच हैं, इनमें 11 थ्री-टियर एसी कोच, 4 टू-टियर एसी कोच और 1 फर्स्ट-क्लास एसी कोच शामिल हैं। इसकी कुल क्षमता लगभग 823 यात्रियों की है।
- गुवाहाटी से शुरू होने वाली ट्रेन में असमिया व्यंजन, जबकि कोलकाता से शुरू होने वाली ट्रेन में बंगाली व्यंजन परोसे जाएंगे।

किफायती दामों पर तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा

164 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं दिसंबर 2025 तक, भारतीय रेलवे नेटवर्क पर।

15 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू कीं वर्ष 2025 के दौरान भारतीय रेलवे ने।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रात भर की यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल देगा। ये लंबी दूरी के यात्रियों के लिए गति, आराम और आधुनिक सुविधाओं का बेहतरीन मेल होंगी।

164 ट्रेनों के नेटवर्क में तब्दील वंदे भारत

दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ। उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास का रहा है। भारत भी उसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में भारत के आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में वंदे भारत की शुरुआत 2019 में सिर्फ एक ट्रेन के साथ हुई थी। आज यह 164 ट्रेनों के नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। ये ट्रेनें हर महीने लाखों यात्रियों को ले जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की गति को और रफ्तार देने के लिए 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की चलाने की घोषणा की थी।

- वंदे भारत ट्रेनें व्यावसायिक यात्रियों की उत्पादकता बढ़ाती हैं।
- ये यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करती हैं।
- सड़क और हवाई यात्रा की तुलना में ये कार्बन उत्सर्जन को भी कम करती हैं।

‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ का प्रतीक वंदे भारत एक्सप्रेस न केवल भारतीय रेलवे की तकनीकी क्षमता का प्रतीक है, बल्कि यह ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की सोच को साकार करती हुई देश की आधुनिक परिवहन व्यवस्था का मजबूत आधार बन रही है। बिहार सहित पूरे देश में यह ट्रेन विकास, कनेक्टिविटी और यात्री सुविधा का नया अध्याय लिख रही है।



15 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी मार्ग पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने

वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस, रेल यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक बड़ा

अत्याधुनिक सुविधाएं एवं सुरक्षा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की विशेषताएं

180 किमी प्रति घंटे तक की गति
वाली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन।

- बेहतर तकिए के साथ एर्गोनॉमिक (ऐसे उत्पाद, जो आरामदायक, सुरक्षित और कुशल हों) रूप से डिजाइन किए गए बर्थ।
- सुगम आवागमन के लिए प्रवेश द्वारों सहित स्वचालित दरवाजे।
- बेहतर सस्पेंशन और शोर कम करने की क्षमता के साथ बेहतर यात्रा।
- सुरक्षा की 'कवच' तकनीक से सुसज्जित।
- उच्च स्वच्छता बनाए रखने के लिए कीटाणुनाशक तकनीक।
- उन्नत नियंत्रण और सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित ड्राइवर केबिन।
- वायुगतिकीय बाहरी बनावट।
- दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था।
- आपातकालीन स्थिति में यात्री और ट्रेन प्रबंधक/लोको पायलट के बीच संचार के लिए आपातकालीन टॉक-बैक यूनिट।
- सभी कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।
- विद्युत कैबिनेट और शौचालयों में एरोसोल आधारित अग्नि पहचान और शमन प्रणाली से अग्नि सुरक्षा में सुधार हुआ है।



अमृत भारत ट्रेन

- अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह से नॉन-एसी ट्रेनें हैं। वर्तमान में 12 स्लीपर और 8 जनरल कोचों के साथ यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
- वर्ष 2026 की शुरुआत में ही 7 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गईं। वर्ष 2025 में 13 ट्रेन चलाई गई थी। भारतीय रेलवे नेटवर्क पर कुल 37 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं।



नमो भारत रैपिड रेल

- नमो भारत रैपिड रेल सेवाएं उच्च आवृत्ति और क्षेत्रीय संपर्क के लिए डिजाइन की गई हैं, जिससे उच्च मांग वाले कॉरिडोर में कम और मध्यम दूरी की आवागमन सुविधा बेहतर होती है।
- देश में भुज-अहमदाबाद और जयनगर-पटना के बीच 2 नमो भारत रैपिड रेल सेवाएं संचालित हैं।

वरदान साबित हुई है। ये भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्रों को जोड़ती है। ये ट्रेनें देश भर के 274 से अधिक

जिलों को सेवा दे रही हैं। इस व्यापक नेटवर्क से पूरे देश में यात्रा, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क में सुधार हो रहा है। ■

संतुलन का खेल है 'वॉलीबॉल'



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। जब देश विकास करता है तो यह सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहता, यह आत्मविश्वास खेल के मैदान पर भी दिखता है। खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है क्योंकि बीते एक दशक से केंद्र सरकार हर स्तर पर खेल के इकोसिस्टम को मजबूती दे रही है। इसी प्रतिबद्धता के तहत आयोजित 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 जनवरी को किया उद्घाटन...

वाराणसी में 4 से 11 जनवरी तक 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें 28 राज्यों और संस्थानों से 58 टीमों के एक हजार से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वॉलीबॉल कोई साधारण खेल नहीं है बल्कि यह संतुलन और सहयोग का खेल है। इस खेल में गेंद को हमेशा हवा में रखने का प्रयास करना पड़ता है इससे दृढ़ संकल्प झलकता है। इस खेल में हर खिलाड़ी 'टीम पहले' के मंत्र से प्रेरित होता है। प्रत्येक खिलाड़ी के पास अलग-अलग कौशल होते हैं लेकिन सभी अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। पीएम मोदी ने भारत के विकास की कहानी और वॉलीबॉल के बीच समानता का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी जीत अकेले प्राप्त नहीं होती बल्कि जीत समन्वय, विश्वास और टीम की तैयारी पर निर्भर करती है। हर किसी की अपनी भूमिका और जिम्मेदारी होती है। सफलता तभी मिलती है जब हर कोई गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को निभाता है।

2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत में आयोजित किए जाएंगे और देश 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भी प्रयासरत है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा करने के बेहतर अवसर प्रदान करना है।

सरकार ने खेल के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। आज भारत का खेल मॉडल 'खिलाड़ी केंद्रित' हो गया है जिसमें प्रतिभा की पहचान, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, पोषण और पारदर्शी चयन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति-2025 भी शामिल है। टॉप्स और खेलो इंडिया जैसी पहल से बहुत बदलाव आ रहा है। ■



मैं तो भारत के विकास की कहानी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातों में समानता देखता हूँ। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत, अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे समन्वय, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



पूर्वोदय के मंत्र का सारथी बन रहा पश्चिम बंगाल

पूर्वोदय, केंद्र सरकार का एक नारा भर नहीं, बल्कि एक मंत्र बन गया है जो पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा में निरंतर नए आयाम जोड़ रहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत से भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की पहल हो या विकास से जुड़ी अन्य परियोजनाएं, पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को नई गति मिली है। बीते 17-18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक तो हुगली के सिंगूर में 830 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास...

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, पूर्वी भारत का भी समान विकास हो, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। इसी संकल्प को और अधिक मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य जनवरी के अपने विशेष दौरे में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात पश्चिम बंगाल को दी। पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यह परिचायक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोदय का मंत्र इस राज्य के विकास में नए अध्याय जोड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की इस पावन भूमि से भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। यहीं से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हुई जो पूरी तरह स्वदेशी है। देश की यह पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि को जोड़ रही है।

पश्चिम बंगाल को, करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली हैं। इन ट्रेनों से बनारस, दिल्ली, तमिलनाडु की यात्रा

le Prime Minister

y, 2026 | West Bengal



सहज होगी। प्रधानमंत्री का दो दिवसीय दौरा पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए अभूतपूर्व रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, “शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा।” पश्चिम बंगाल की प्रगति को गति देने का अभियान और तेज हुआ है। इन परियोजनाओं से यहां के लोगों के लिए यात्रा और कारोबार भी आसान बनेगा। राज्य के नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

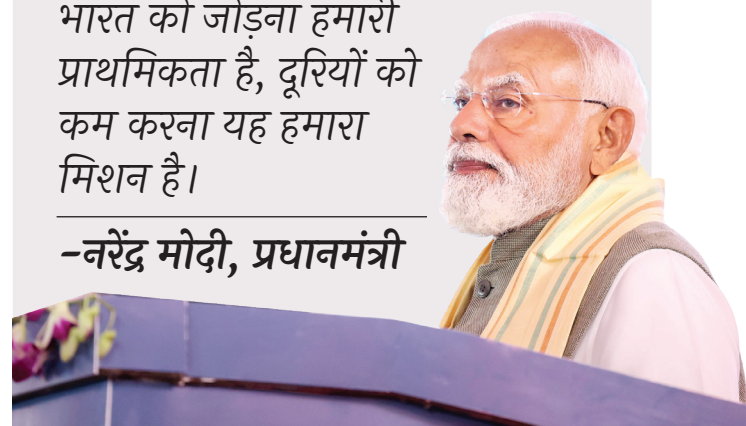


प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



भारत को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है, दूरियों को कम करना यह हमारा मिशन है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री





विकास की पटरी पर दौड़ता पश्चिम बंगाल

4,080

करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न रेल और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास -शुभारंभ मालदा और हुगली में।

- हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी।
- बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास, इससे अंतर्देशीय जल परिवहन और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
- कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामरान का भी शुभारंभ। यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित 6 इलेक्ट्रिक कैटामरानों में से एक है।
- 7 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी, जिससे पश्चिम बंगाल का अन्य राज्यों के साथ रेल संपर्क मजबूत होगा।
- यह ट्रेने हैं-नई जलपाईगुड़ी-नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस; नई जलपाईगुड़ी-तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार-एसएमवीटी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस; अलीपुरद्वार-मुंबई (पनवेल) अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता (हावड़ा)-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस; कोलकाता (सियालदह)-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस; कोलकाता (संतरागाछी)-ताम्बरम अमृत भारत एक्सप्रेस।
- पश्चिम बंगाल में चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें बलुरघाट और हिली के बीच नई रेल लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी में अगली पीढ़ी की माल दुलाई रखरखाव सुविधाएं, सिलीगुड़ी लोको शेड का उन्नयन और जलपाईगुड़ी जिले में वंदे भारत ट्रेन रखरखाव सुविधाओं का आधुनिकीकरण शामिल है।
- न्यू कूचबिहार-बमनहाट और न्यू कूचबिहार-बॉक्सरहाट के बीच रेल लाइनों का विद्युतीकरण राष्ट्र को समर्पित। एलएचबी कोचों से सुसज्जित दो नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई।
- जयरामबती-बरोगोपीनाथपुर-मयनापुर नई रेल लाइन का भी उद्घाटन।
- राष्ट्रीय राजमार्ग-31डी के धूपगुड़ी-फलाकाटा खंड के पुनर्निर्माण और चार लेन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी।



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

इस राज्य में जलमार्ग के लिए बेहतर संभावनाएं हैं, जिस दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। यह केवल पश्चिम बंगाल के विकास के लिए नहीं, बल्कि भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह स्तंभ हैं जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैनुफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। आज भारत में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी पर बहुत जोर दिया जा रहा है। परिवहन सहज हो, इसके लिए पोर्ट, नदी जलमार्ग, हाईवे और एयरपोर्ट, इन सभी को आपस में जोड़ा जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत और परिवहन में लगने वाले समय, दोनों में कमी आ रही है। भारत आज फिशरीज और सी-फूड के उत्पादन और निर्यात में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री का सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश का नेतृत्व करे।

आधुनिकता भी, आत्मनिर्भरता भी

भारतीय रेल आधुनिक होने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भी हो रही है। रेलवे का बिजलीकरण हो रहा है, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। भारत के रेल इंजन, भारत के रेल के डिब्बे, भारत के मेट्रो कोच, ये सब भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान बन रहे हैं। आज अमेरिका और यूरोप से ज्यादा लोकोमोटिव भारत में बन रहे हैं। दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के कोच का निर्यात भारत करने लगा है, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ और नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल सहित देश में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। इसके साथ-साथ आधुनिक और तेज गति की ट्रेनों का पूरा नेटवर्क बन रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ पश्चिम बंगाल के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को हो रहा है। ■



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

इकोनॉमी और इकोलॉजी का नया अध्याय लिख रहा असम

भारत आज प्रकृति और प्रगति को साथ लेकर आगे बढ़ने की मिसाल बन रहा है। जनवरी के मध्य में असम के कालियाबोर में लगभग 7 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन इसका उम्दा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जैव विविधता के अनमोल रत्न- काजीरंगा के लिए इस विशेष परियोजना की शुरुआत की और विकास की अन्य परियोजनाओं के साथ असम की सांस्कृतिक गौरव के भी बने साक्षी...

भारत के विकास का इंजन- पूर्वोत्तर, जिसकी एक पीड़ा थी- दूरी की। दूरी दिलों की, दूरी स्थानों की। दशकों तक, यहां के लोगों को यही महसूस होता रहा कि देश का विकास कहीं और हो रहा है और वह पीछे छूट रहे हैं। इसका असर केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, बल्कि भरोसे पर भी पड़ा। इस भावना को बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो स्वयं पूर्वोत्तर का 70 से अधिक दौरा कर चुके हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर के विकास को प्राथमिकता बनाया। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज के माध्यम से, असम को जोड़ने पर एक साथ काम शुरू किया और आज परिणाम सामने है कि पूर्वोत्तर और उसका गेट-वे 'असम' विकास की नई गाथा लिख रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ा रही है- काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना। काजीरंगा

“

कनेक्टिविटी का ये विस्तार भरोसा पैदा करता है कि नॉर्थ ईस्ट अब विकास के हाशिए पर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

और यहां के वन्यजीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह असम के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के प्रति दायित्व

असम को विकास की सौगात

- कलियाबोर में 6 हजार 950 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 86 किलोमीटर लंबी काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन।
- इसमें 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वन्यजीव गलियारा शामिल होगा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। साथ ही 21 किलोमीटर का बाईपास खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-715 के मौजूदा राजमार्ग खंड का 30 किलोमीटर तक विस्तार कर इसे दो लेन से उन्नत कर चार लेन का बनाया जाएगा।
- गुवाहाटी (कामाख्या)-रोहतक और डिब्रूगढ़-लखनऊ (गोमती नगर) के बीच चलाई जाने वाली दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई।
- बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दहोउ 2026 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बोडो समुदाय के 10 हजार से अधिक कलाकारों ने बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत किया।
- बागुरुम्बा नृत्य शांति, उर्वरता, आनंद और सामूहिक सद्भाव का प्रतीक है और बोडो नव वर्ष ब्विसागु और डोमासी जैसे त्योहारों से निकटता से जुड़ा हुआ है।



बागुरुम्बा दहोउ ने बनाया रिकॉर्ड

पूर्वोत्तर, अब दिल्ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में है। जनवरी के मध्य में प्रधानमंत्री मोदी जब असम में विकास परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे थे, तो उनका यह प्रेम हर बार की तरह इस बार भी स्पष्ट रूप से दिखा। इस कार्यक्रम बोडो समुदाय की बेटियों ने बागुरुम्बा की प्रस्तुति देकर नया रिकॉर्ड बनाया। बागुरुम्बा की ऐसी अद्भुत प्रस्तुति, दस हजार से अधिक कलाकारों की ऊर्जा, खाम की थाप, सिफुन्ग की धुन, उन मनोरम पलों ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बागुरुम्बा की अनुभूति आंखों से होकर दिल में उतरती रही जो 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को और मजबूत करता है। 'बागुरुम्बा दहोउ' ये केवल एक उत्सव नहीं है। यह एक माध्यम है- महान बोडो परंपरा को सम्मान देने का।



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

भी है। काजीरंगा केवल एक नेशनल पार्क नहीं है, यह असम की आत्मा है। भारत की जैव-विविधता का एक अनमोल रत्न भी है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है।

इसलिए जरूरी थी यह परियोजना

काजीरंगा एक-सींग वाले राइनो का घर है। हर साल बाढ़ के समय जब ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ता है, तब यहीं सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। तब वन्यजीव ऊंचे इलाकों की तलाश में निकलते हैं। इसी रास्ते में उन्हें नेशनल हाइवे पार करना पड़ता है। ऐसे समय में राइनो, हाथी और हिरण सड़क के किनारे फंस जाते हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि सड़क भी चलती रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। इसी विजन के तहत, कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया गया है। इस पर लगभग 7 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें लगभग 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर भी बनेगा। कॉरिडोर

को एक-सींग वाला राइनो, हाथी, बाघ जैसे जानवरों के पारंपरिक मूवमेंट रूट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह कॉरिडोर ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा।

असम: पूर्वोत्तर के विकास का प्रवेश द्वार

असम का विकास पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। जब रेल कनेक्टिविटी बढ़ता है तो इसका लाभ सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए पूर्वोत्तर के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। पहले असम को केवल 2 हजार करोड़ रुपये का रेल बजट मिलता था, अब वह बढ़कर 10 हजार करोड़ रुपये हो चुका है। इस बढ़े हुए निवेश से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हुआ है। कलियाबोर से जिन तीन नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ जनवरी 2026 में हुआ है, वह असम की रेल कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। ■



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

पूरी मानवता को भगवान बुद्ध का ज्ञान

भारत, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए प्रतिबद्ध है। भगवान बुद्ध ने हमें यही सिखाया। भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनके दिखाए मार्ग, पूरी मानवता का है और कालातीत है जो समय के साथ बदला नहीं। भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा के पवित्र अवशेषों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का किया उद्घाटन...

भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है। पिपरहवा, वैशाली, देवनी मोरी और नागार्जुनकोण्डा से प्राप्त भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष, बुद्ध के संदेश की जीवित उपस्थिति हैं। भारत ने इन अवशेषों को साइंस और आध्यात्म के हर रूप में संभाला और सहेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। मेरा जन्म जिस वडनगर में हुआ वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए वो सारनाथ आज मेरी कर्मभूमि है। जब मैं सरकार के दायित्वों से दूर था तब

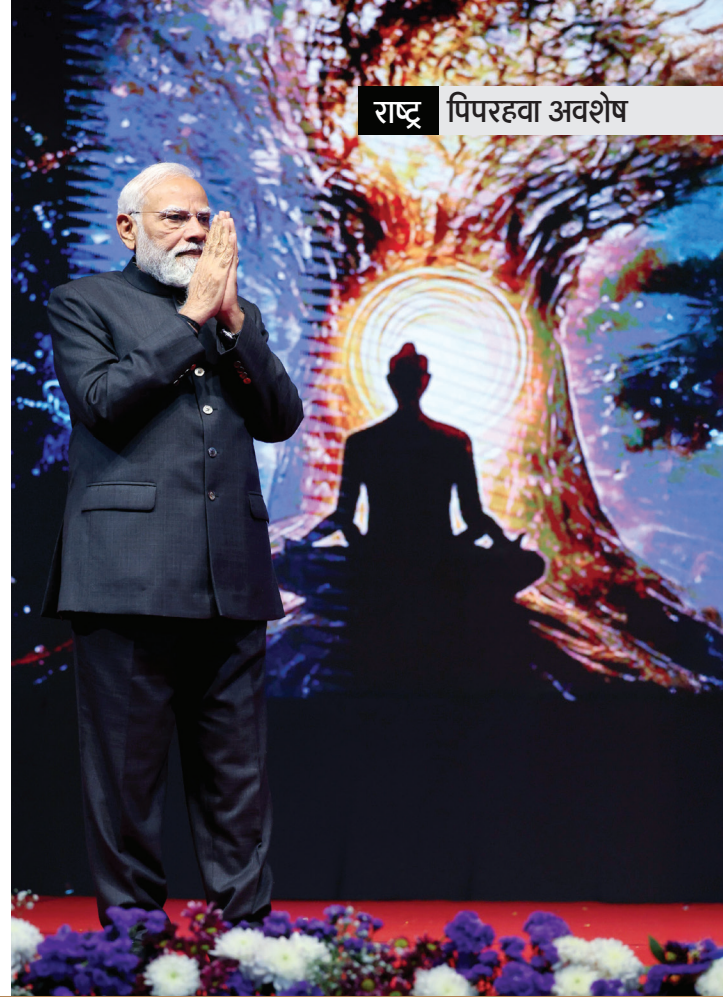
“

भगवान बुद्ध ने दुनिया को संघर्ष और प्रभुत्व की बजाय, साथ चलने का रास्ता दिखाया। यही भारत की मूल सोच रही है। हमने विचारों के बल पर, संवेदनाओं के धरातल पर, मानवता के हित में ही विश्व कल्याण का मार्ग अपनाया है। इसी सोच के साथ भारत, 21वीं सदी की दुनिया में अपना योगदान दे रहा है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

एक सदी के बाद देश वापस लाया गया पिपरहवा अवशेष

- प्रदर्शनी को पहली बार पिपरहवा से संबंधित प्रमाणिक अवशेषों और पुरातात्विक सामग्री के साथ प्रस्तुत किया गया।
- 1898 में खोजे गए पिपरहवा अवशेषों का प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये सबसे शुरुआती और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक हैं जो सीधे भगवान बुद्ध से जुड़े हैं।
- पुरातात्विक साक्ष्य पिपरहवा स्थल को प्राचीन कपिलवस्तु से जोड़ते हैं। प्रदर्शनी भारत के भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ गहरे एवं निरंतर सम्यतागत संबंध को उजागर करती है।
- लगातार सरकारी प्रयास, संस्थागत सहयोग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इन पवित्र अवशेषों की हाल ही में वापसी संभव हो पाई।
- अन्य अनुभागों में 'पिपरहवा को पुनः जाने', 'बुद्ध के जीवन की झलकियाँ' सहित अन्य चीजें शामिल रही।
- इस प्रदर्शनी में ऑडियो-विजुअल को व्यापक रूप से शामिल किया गया। प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के जीवन की जानकारी मिलती है।



दुनिया में बौद्ध विरासत से जुड़े स्थल के निरंतर विकास के लिए भारत प्रयासरत

- नेपाल में आए भीषण भूकंप ने प्राचीन स्तूपों को नुकसान पहुंचाया तो भारत ने इसके पुनर्निर्माण में सहयोग दिया।
- म्यांमार के बागान में आए भूकंप के बाद, भारत ने 11 से अधिक पगोडाओं का संरक्षण किया।
- गुजरात का वडनगर में एक शानदार म्यूजियम बनाया गया है जो करीब 2,500 वर्ष के इतिहास का अनुभव देता है।
- जम्मू-कश्मीर के बारामूला में बौद्ध काल की प्रमुख बुद्धिस्ट साइट का पता चला है। अब इसके संरक्षण का काम तेज किया जा रहा है।
- बोधगया में कन्वेंशन सेंटर और मेडिटेशन व एक्सपीरियंस सेंटर।
- श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया।
- सांची, नागार्जुन सागर, अमरावती जगहों पर तीर्थयात्रियों के लिए नई सुविधाएं विकसित की गई हैं।
- देश में एक बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है ताकि भारत के सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी हो।
- भगवान बुद्ध के अभिधम्म, वाणी, शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में हैं। जन सामान्य तक पाली भाषा पहुंचाने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने इसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है।

भी मैं एक तीर्थयात्री के रूप में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता रहता था। प्रधानमंत्री के रूप में तो मुझे दुनियाभर में बौद्ध तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिला है।

सवा सौ साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत, धरोहर लौटी है। अब भारतीय जन-मानस, भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जहां-जहां गया, मेरा प्रयास रहा कि भगवान बुद्ध की विरासत का एक प्रतीक वहां के लोगों के बीच में जोड़कर लौटूं। इसलिए चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया बोधि वृक्ष के पौधे लेकर गया था।

भारत के गौरवशाली इतिहास की यशभूमि किला राय पिथौरा

भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी जिस स्थान पर लगी, वो अपने आप में विशेष है। किला राय पिथौरा का स्थान, भारत के गौरवशाली इतिहास की यशभूमि में शामिल है। इस ऐतिहासिक किले के इर्द-गिर्द, लगभग एक हजार साल पहले, उस समय के पूर्व शासकों ने एक दृढ़ और मजबूत सुरक्षित दीवारों से घिरे नगर की स्थापना की थी। उसी ऐतिहासिक नगर परिसर में, इतिहास की एक आध्यात्मिक और पुण्य गाथा को जोड़ा गया। ■



भारत ने विविधता को बना दिया लोकतंत्र की ताकत

भारत में लोकतंत्र का अर्थ, लास्ट माइल डिलीवरी है। यही कारण है कि केंद्र सरकार लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है, जिसके कारण बीते कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूती देने की कड़ी में संसद भवन परिसर में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को किया उद्घाटन...

जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में यह आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी विविधता में, यहां लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी विविधता को लोकतंत्र की ताकत बना दिया। भारत में डेमोक्रेसी इसलिए डिलीवर करती है, क्योंकि यहां देश की जनता ही सर्वोपरि है। राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने जनता-जनार्दन के सपनों को प्राथमिकता बनाया है। उसके रास्ते में कोई बाधा न आए, इसके लिए प्रक्रिया से लेकर टेक्नोलॉजी तक, हर चीज का लोकतंत्रीकरण किया है। यह लोकतांत्रिक भावना हमारी रगों, मन और संस्कार में शामिल है। लोगों का हित, भलाई और उनका कल्याण, यह हमारा संस्कार है और यह संस्कार लोकतंत्र ने दिए हैं।

“
भारत ने यह साबित किया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं लोकतंत्र को स्थिरता, गति और व्यापकता प्रदान करती हैं।

—नरेंद्र मोदी,
प्रधानमंत्री





कसौटी पर परखे गए हैं भारत के लोकतांत्रिक मूल्य

तमिलनाडु से 10वीं सदी का एक शिलालेख मिला है। इसमें एक ग्राम सभा का वर्णन है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ काम करती थी। जवाबदेही और फैसले लेने के लिए स्पष्ट नियम थे। समय-समय पर भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कसौटी पर परखा गया है। विविधता ने इन्हें सहारा दिया है और पीढ़ी दर पीढ़ी यह मजबूत होते गए हैं। दुनिया भर में लोग भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। इसे लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। देश में वाद-विवाद, संवाद और सामूहिक निर्णय लेने की लंबी परंपरा रही है। भारत के 5,000 वर्ष से अधिक पुराने पवित्र ग्रंथों एवं वेदों में उन सभाओं का उल्लेख है जहां लोग मुद्दों पर चर्चा करने और विचार-विमर्श एवं सहमति के बाद निर्णय लेने के लिए एकत्रित होते थे।

लोकसभा अध्यक्ष ने कई संसदीय नेताओं के साथ किए द्विपक्षीय संवाद

सम्मेलन के इतर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई प्रतिष्ठित संसदीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय संवाद किए। इनमें कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष, श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष, सेशेल्स की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष, मालदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष, केन्या की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, ग्रेनेडा की सीनेट की अध्यक्ष, दक्षिण अफ्रीका की नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविसेंस के उपाध्यक्ष और दक्षिण अफ्रीका की नेशनल असेंबली की उपाध्यक्ष शामिल हैं।



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

राष्ट्रमंडल देशों की कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा भारत में रहता है। राष्ट्रमंडल देशों के सतत विकास लक्ष्यों में भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब ग्लोबल

साउथ के लिए भी यह नया रास्ता बनाने का समय है। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। भारत का यह लगातार प्रयास है कि यहां जो भी इनोवेशन करें, उससे पूरे ग्लोबल साउथ और कॉमनवेल्थ देशों को फायदा हो। ■

दुनिया में भारत का परचम



भारत में **UPI**
दुनिया का सबसे
बड़ा डिजिटल
पेमेंट सिस्टम है।



भारत दुनिया
का सबसे बड़ा
वैक्सीन उत्पादक
देश है।



भारत दुनिया
का सबसे बड़ा
दूध उत्पादक
देश है।



भारत दुनिया
का नंबर-
2 स्टील
उत्पादक है।



भारत में दुनिया
का तीसरा सबसे
बड़ा स्टार्टअप
इकोसिस्टम है।



भारत दुनिया का
तीसरा सबसे
बड़ा एविएशन
मार्केट है।



भारत में दुनिया
का चौथा
सबसे बड़ा रेल
नेटवर्क है।



भारत में दुनिया
का तीसरा सबसे
बड़ा मेट्रो रेल
नेटवर्क है।



राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस- 16 जनवरी

स्टार्टअप इंडिया... सिर्फ स्कीम नहीं, रेनबो विजन

भारत आज दुनिया में स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और यह स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद बीते एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा किए कई रिफॉर्म का नतीजा है। सरकार की नीतियों की वजह से स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी कदम रखने का अनुकूल वातावरण बना। स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े सदस्यों से किया संवाद...

भारत को नौकरी मांगने वालों के बजाय नौकरी देने वालों का देश बनाने के साथ, नवाचार को बढ़ावा देना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और निवेश से होने वाले विकास को सक्षम बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ किया। पिछले एक दशक में, स्टार्टअप इंडिया भारत के आर्थिक और नवाचार ढांचे का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत किया है, पूंजी और मेंटरशिप तक पहुंच बढ़ाई है। बीते एक दशक में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है।

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर स्टार्टअप इंडिया के एक दशक को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “मैं नए और विकसित होते भारत का भविष्य देख रहा हूं।” यह शब्द स्टार्टअप इंडिया की 10 वर्ष की सफलता की कहानी है। 10 साल पहले, विज्ञान भवन में 500-700 नौजवानों



हमने स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब बनाए, ताकि वहां बच्चों में इनोवेशन की प्रवृत्ति बने। हमने हैकाथॉन शुरू किए, ताकि हमारे युवा देश की समस्याओं का समाधान दे सकें। हमने इन्क्यूबेशन सेंटर बनाए, ताकि संसाधनों की कमी से आइडिया की डेथ न हो।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

के बीच में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी जबकि एक दशक की यात्रा का उत्सव मनाने के लिए 16 जनवरी, 2026 को इतने उत्साही लोग जुटे कि भारत मंडपम में जगह नहीं बची।

पीएम मोदी का मंत्र...परिश्रम की पराकाष्ठा से मिलती है नई मंजिल

नई मंजिल के लिए हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखानी होती है। हमारे यहां कहा जाता है- उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, कार्याणि न मनोरथैः। अर्थात्, कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से नहीं होता। उद्यम के लिए पहली शर्त है- साहस। पहले देश में रिस्क टेकिंग को हतोत्साहित किया जाता था, आज यह मेन स्ट्रीम बन गया है। मासिक सैलरी से आगे सोचने वाले को अब केवल स्वीकार ही नहीं किया जाता बल्कि उसे सम्मानित किया जाता है। जिन रिस्क टेकिंग आइडिया को पहले लोग फ्रिज यानी मुख्यधारा से अलग मानते थे, वो अब फैशन बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं की तरह जोखिम लेना पसंद है। जिन कामों के लिए लोग आकर कहते थे, इसमें बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं। मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है, वो किसी न किसी को तो करना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा, तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा।



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया कि यह जर्नी, सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये हजारों-लाखों सपनों की जर्नी है। 10 साल पहले व्यक्तिगत प्रयास और नवाचार के लिए बहुत गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज किया, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया। युवाओं को एक खुला आसमान दिया, आज नतीजा सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक क्रांति बन चुका है। भारत आज दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। दस साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज यह संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ चार यूनिकॉर्न थे, आज करीब सवा सौ एक्टिव यूनिकॉर्न हैं।

भारत में 2025 में करीब 44 हजार और नए स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। यह स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल में सबसे बड़ा जंप है। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनोवेशन और ग्रोथ को किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। पहले बिजनेस या नया बेंचर बड़े घरानों के बच्चे लेकर

आते थे अब ऐसा नहीं है। टियर-2 और टियर-3 शहर एवं गांव के युवा अपने स्टार्टअप खोल रहे हैं। आज 45 फीसदी से ज्यादा स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है तो वहीं महिला के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की फंडिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम भी है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक 'रेनबो विजन' है। ये अलग-अलग क्षेत्रों को नई संभावनाओं से जोड़ने का जरिया है। ऐसे में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी आकांक्षा सिर्फ पार्टनरशिप की नहीं रहनी चाहिए। हमें वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य रखना होगा। आप नए आइडियाज पर काम करें, समस्याओं का समाधान करें। अब समय है कि हमारे स्टार्टअप मैनुफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान दें। टेक्नोलॉजी में भी यूनिक आइडिया पर काम करके लीड लेनी होगी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, आने वाले दस वर्षों में भारत नए स्टार्टअप ट्रेंड और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे। ■



गणतंत्र दिवस...

स्वाधीनता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्य का प्रतीक

गणतंत्र दिवस, लोकतंत्र को सशक्त बनाने, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और विकसित भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने की प्रेरणा देता है। साथ ही यह पर्व एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की नई ऊर्जा देता है। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्र को संबोधित किया। पेश है संबोधन के संपादित अंश...

संविधान: सबसे बड़े गणराज्य का आधार-ग्रंथ

हमारा संविधान, विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्य का आधार-ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीयता की भावना एवं देश की एकता को संवैधानिक प्रावधानों का सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने हमारे राष्ट्र का एकीकरण किया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हमारी प्राचीन सांस्कृतिक एकता का ताना-बाना हमारे पूर्वजों ने बुना था। राष्ट्रीय एकता के स्वरूपों को जीवंत बनाए रखने का प्रत्येक प्रयास अत्यंत सराहनीय है।

वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष

पिछले वर्ष, 7 नवंबर से, राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उत्सव मनाए जा रहे हैं। भारत माता के दैवी स्वरूप की वंदना का यह गीत, जन-मन में राष्ट्र-प्रेम का संचार करता है। राष्ट्रीयता के महाकवि सुब्रमण्य भारती ने तमिल भाषा में 'वंदे मातरम् येन्बोम्' अर्थात् 'हम वंदे मातरम् बोलें' इस गीत की रचना करके वंदे मातरम् की भावना को और भी व्यापक स्तर पर जनमानस के साथ जोड़ा। अन्य भारतीय भाषाओं में भी इस गीत के अनुवाद लोकप्रिय हुए। श्री ऑरोबिंदो ने 'वंदे मातरम्' का अंग्रेजी अनुवाद किया। ऋषितुल्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 'वंदे मातरम्' हमारी राष्ट्र-वंदना का

स्वर है। वर्ष 2021 से नेताजी की जयंती को 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाया जाता है ताकि देशवासी, विशेषकर युवा, उनकी अदम्य देशभक्ति से प्रेरणा प्राप्त करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा 'जय हिंद' हमारे राष्ट्र-गौरव का उद्घोष है।

जीवंत गणतंत्र को बना रहे हैं शक्तिशाली

हमारी तीनों सेनाओं के बहादुर जवान, मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। हमारे कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान, देशवासियों की आंतरिक सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अन्नदाता किसान, देशवासियों के लिए पोषण सामग्री उत्पन्न करते हैं। देश की कर्मठ और प्रतिभाशाली महिलाएं अनेक क्षेत्रों में नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। सेवाधर्मी डॉक्टर, नर्स और सभी स्वास्थ्य-कर्मि देशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। निष्ठावान सफाई मित्र, देश को स्वच्छ रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रबुद्ध शिक्षक, भावी पीढ़ियों का निर्माण करते हैं। विश्व-स्तरीय वैज्ञानिक और इंजीनियर, देश के विकास को नई दिशाएं देते हैं। मेहनती श्रमिक भाई-बहन, राष्ट्र का नव-निर्माण करते हैं। होनहार युवा और बच्चे, अपनी प्रतिभा और योगदान से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति विश्वास मजबूत करते हैं। प्रतिभाशाली कलाकार, शिल्पकार और साहित्यकार, समृद्ध परंपराओं को आधुनिक अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञ, देश के बहुआयामी विकास को दिशा दे रहे हैं। ऊर्जावान उद्यमी, देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

महिलाओं का सक्रिय और समर्थ होना देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान से बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। 'प्रधानमंत्री-जन धन योजना' के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें महिलाओं के खाते लगभग 56 प्रतिशत हैं। बहनें और बेटियां, परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या लगभग 46 प्रतिशत है। महिलाओं के राजनैतिक सशक्तीकरण को नई ऊंचाई देने वाले 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' से महिलाओं के नेतृत्व द्वारा विकास की सोच को अभूतपूर्व शक्ति मिलेगी।

'आदि कर्मयोगी' अभियान

'आदि कर्मयोगी' अभियान के माध्यम से, जनजातीय समुदाय के लोगों में नेतृत्व क्षमता को निखारा गया। विगत वर्षों में सरकार ने, जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास से देशवासियों का परिचय कराने के लिए संग्रहालयों के निर्माण सहित अनेक कदम उठाए हैं। उनके कल्याण और विकास को प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा के कई अभियान जनजातीय समुदायों की विरासत और विकास का समन्वय कर रहे हैं।

डिजिटल पेमेंट

हमारे देशवासियों ने डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया है। आज विश्व के आधे से अधिक डिजिटल लेनदेन भारत में होते हैं। छोटी से छोटी दुकान में सामान खरीदने से लेकर ऑटो-रिक्शा का किराया देने तक, डिजिटल भुगतान का उपयोग विश्व समुदाय के लिए प्रभावशाली उदाहरण बन गया है।

ऑपरेशन सिंदूर

पिछले वर्ष, हमारे देश ने, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, आतंकवाद के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। आतंक के अनेक ठिकानों को ध्वस्त किया गया तथा बहुत से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता से ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को शक्ति मिली।

यह हमारा सौभाग्य है कि हम भारत-भूमि के निवासी हैं। हमारी जननी जन्मभूमि के लिए कवि गुरु रवींद्र नाथ ठाकुर ने कहा था: ओ आमार देशेर माटी, तोमार पोरे ठेकाइ माथा।

अर्थात्, हे मेरे देश की माटी! मैं तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ।

मैं मानती हूँ कि गणतंत्र दिवस, देशभक्ति की इस प्रबल भावना को और भी सुदृढ़ करने के संकल्प का अवसर है। आइए, हम सब मिलकर 'राष्ट्र प्रथम' की भावना से कार्य करते हुए अपने गणतंत्र को और भी गौरवशाली बनाएं। ■



शौर्य, सामर्थ्य और संस्कृति के साथ गूंजा

वन्दे मातरम्

77वां गणतंत्र दिवस भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता, संवैधानिक मूल्यों की दृढ़ता और राष्ट्र की प्रगतिशील यात्रा का भव्य उत्सव बनकर सामने आया। कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड ने भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्भर भारत की झलक को एक साथ प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति के अभिवादन से लेकर तीनों सेना की अनुशासित टुकड़ियों, अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों और राज्यों की जीवंत झांकियों तक, हर दृश्य राष्ट्र गौरव से ओतप्रोत रहा। इस फोटो फीचर में गणतंत्र दिवस के वे अविस्मरणीय क्षण संजोए गए हैं, जो भारत की एकता, अखंडता और निरंतर प्रगति की कहानी को करते हैं जीवंत...



77वें गणतंत्र दिवस की पूरी परेड
देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया।



77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर नागरिकों का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।



गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक की तरफ रक्षा मंत्री और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।



इस वर्ष के परेड का विषय 'वंदे मातरम के 150 साल' रहा।





राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ गणतंत्र दिवस परेड 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन।



ऑपरेशन सिंदूर की झांकी जिसमें पाकिस्तान के भीतर किए गए सटीक आतंकवाद-रोधी हमलों को दिखाया गया।



पहली बार, जम्मू-कश्मीर की बेटी सिमरन बाला ने सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व किया।



देश के कोने-कोने से आए कलाकारों ने भारत की आत्मा को कर्तव्य पथ पर किया जीवंत।



समृद्धि का मंत्र: आत्मनिर्भर भारत, प्रदर्शित करती तमिलनाडु की झांकी।



वॉटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता: आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल।



करतब दिखाते सेना के जवान।

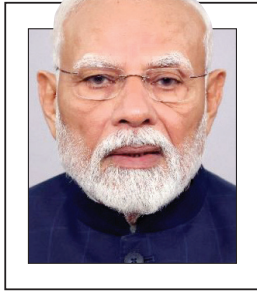


स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल की भूमिका को प्रस्तुत करती झांकी।



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकी।

एक भारत, श्रेष्ठ भारत का जीवंत प्रतीक है काशी-तमिल संगमम



 नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

काशी का तमिल समाज और संस्कृति से अत्यंत गहरा नाता रहा है। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो तमिलनाडु में रामेश्वरम तीर्थ है। तमिलनाडु की तेनकासी को दक्षिण की काशी या दक्षिण काशी कहा जाता है।



प्रधानमंत्री का आलेख पढ़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।

विश्व की सबसे पुरानी भाषा और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक, इन दोनों का संगम हमेशा अद्भुत रहा है। काशी तमिल संगमम ऐसे ही एक रिश्ते का जश्न है जो सदियों से भारतीय कल्पना में बसा हुआ है। अनगिनत तीर्थयात्रियों, विद्वानों और साधकों के लिए तमिलनाडु और काशी के बीच की यात्रा कभी भी सिर्फ शारीरिक तौर पर आने-जाने का रास्ता नहीं था बल्कि यह विचारों, भाषाओं और जीवित परंपराओं का एक आंदोलन था। एक भारत, श्रेष्ठ भारत का जीवंत प्रतीक काशी-तमिल संगमम पर पढ़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आलेख...

कुछ दिन पहले ही मुझे सोमनाथ की पवित्र भूमि पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने का सुअवसर मिला। इस पर्व को हम वर्ष 1026 में सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार साल पूरे होने पर मना रहे हैं। इस क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने-कोने से लोग सोमनाथ पहुंचे। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतवर्ष के लोग जहां अपने इतिहास और संस्कृति से गहराई से जुड़े हैं, वहीं कभी हार न मानने वाला साहस भी उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता है। यही भावना उन्हें एक साथ जोड़ती भी है। इस कार्यक्रम के दौरान मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी हुई जो इससे पहले सौराष्ट्र-तमिल संगमम के दौरान सोमनाथ आए थे और इससे पहले काशी-तमिल संगमम के समय काशी भी गए थे। ऐसे मंचों को लेकर उनकी सकारात्मक सोच ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसलिए मैंने तय किया कि क्यों न इस विषय पर अपने कुछ विचार साझा करूं।

‘मन की बात’ के एक एपिसोड के दौरान मैंने कहा था कि अपने जीवन में तमिल भाषा न सीख पाने का मुझे बहुत दुख है। यह हमारा सौभाग्य है कि बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार तमिल संस्कृति को देश में और लोकप्रिय बनाने में निरंतर जुटी हुई है। यह ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को और सशक्त बनाने वाला है। हमारी संस्कृति में संगम का



बहुत महत्त्व है। इस पहलू से भी काशी-तमिल संगमम एक अनूठा प्रयास है। इसमें जहां भारत की विविध परंपराओं के बीच अद्भुत सामंजस्य दिखता है, वहीं यह भी पता चलता है कि कैसे हम एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं।

काशी तमिल संगमम के आयोजन के लिए काशी सबसे उपयुक्त स्थान कहा जा सकता है। यह वही काशी है जो अनादि काल से हमारी सभ्यता की धुरी बनी हुई है। यहां हजारों वर्षों से लोग ज्ञान, जीवन के अर्थ और मोक्ष की खोज में आते रहे हैं।

काशी का तमिल समाज और संस्कृति से अत्यंत गहरा नाता रहा है। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो तमिलनाडु में रामेश्वरम तीर्थ है। तमिलनाडु की तेनकासी को दक्षिण की काशी या दक्षिण काशी कहा जाता है। पूज्य कुमारगुरुपरस्वामिजी ने अपनी विद्वता और आध्यात्म परंपरा के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच एक सशक्त और स्थायी संबंध स्थापित किया था।

तमिलनाडु के महान सपूत महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी को भी काशी में बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक जागरण का अद्भुत अवसर दिखा। यहीं उनका राष्ट्रवाद और प्रबल हुआ, साथ ही उनकी कविताओं को एक नई धार मिली। यहीं पर स्वतंत्र और अखंड भारत की उनकी संकल्पना को एक स्पष्ट दिशा मिली। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जो काशी और तमिलनाडु के बीच गहरे आत्मीय संबंध को दर्शाते हैं।

वर्ष 2022 में वाराणसी की धरती पर काशी-तमिल संगमम की शुरुआत हुई थी। मुझे इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला था। तब तमिलनाडु से आए लेखकों, विद्यार्थियों, कलाकारों, विद्वानों, किसानों और अतिथियों ने काशी के साथ साथ प्रयागराज और अयोध्या के दर्शन भी किए थे। इसके बाद के आयोजनों में इस पहल को और विस्तार दिया गया।

इसका उद्देश्य यह था कि संगमम में समय-समय पर नए

विषय जोड़े जाएं, नए और रचनात्मक तरीके अपनाए जाएं और इसमें लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। प्रयास यह था कि ये आयोजन अपनी मूल भावना से जुड़े रहकर भी निरंतर आगे बढ़ता रहे। वर्ष 2023 के दूसरे आयोजन में टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो कि भाषा इसमें बाधा न बने। इसके तीसरे संस्करण में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर विशेष फोकस रखा गया। इसके साथ ही शैक्षिक संवादों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, प्रदर्शनियों और संवाद सत्रों में लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। हजारों लोग इनका हिस्सा बने।

काशी-तमिल संगमम का चौथा संस्करण 2 दिसंबर, 2025 को आरंभ हुआ। इस बार की थीम बहुत रोचक थी- तमिल करकलम् यानि तमिल सीखें...

इससे काशी और दूसरी जगहों के लोगों को खूबसूरत तमिल भाषा सीखने का एक अनूठा अवसर मिला। तमिलनाडु से आए शिक्षकों ने काशी के विद्यार्थियों के लिए इसे अविस्मरणीय बना दिया! इस बार कई और विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

प्राचीन तमिल साहित्य ग्रंथ तोलकाप्पियम का चार भारतीय और छह विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया।

तेनकासी से काशी तक पहुंची एक विशेष व्हीकल एक्सपेडिशन भी देखने को मिली। इसके अलावा काशी में स्वास्थ्य शिविरों और डिजिटल लिटरेसी कैंप के आयोजन के साथ ही कई और सराहनीय प्रयास भी किए गए। इस अभियान में सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रसार करने वाले पांड्य वंश के महान राजा आदि वीर पराक्रम पांडियन जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

पूरे आयोजन के दौरान नमो घाट पर प्रदर्शनियां लगाई गईं, बीएचयू में शैक्षणिक सत्र का आयोजन हुआ, साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए।

काशी-तमिल संगमम में इस बार जिस चीज ने मुझे सबसे

अधिक प्रसन्नता दी, वो हमारे युवा साथियों का उत्साह है। इससे अपनी जड़ों से और अधिक जुड़े रहने के उनके पैशन का पता चलता है। उनके लिए ये एक ऐसा अद्भुत मंच है, जहां वे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं।

संगमम के अलावा काशी की यात्रा भी यादगार बने, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए। भारतीय रेल ने लोगों को तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई। इस दौरान कई रेलवे स्टेशनों पर, विशेषकर तमिलनाडु में उनका खूब उत्साह बढ़ाया गया। सुंदर गीतों और आपसी चर्चाओं से ये सफर और आनंददायक बन गया।

यहां मैं काशी और उत्तर प्रदेश के अपने भाइयों और बहनों की सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने काशी-तमिल संगमम को विशेष बनाने में अपना अद्भुत योगदान दिया है। उन्होंने अपने अतिथियों के स्वागत और सत्कार में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। कई लोगों ने तमिलनाडु से आए अतिथियों के लिए अपने घरों के दरवाजे तक खोल दिए। स्थानीय प्रशासन भी चौबीसों घंटे जुटा रहा, ताकि मेहमानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। वाराणसी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये गर्व और संतोष दोनों का विषय है।

इस बार काशी-तमिल संगमम का समापन समारोह रामेश्वरम में आयोजित किया गया, जिसमें तमिलनाडु के संपूत उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी भी मौजूद रहे। उन्होंने

इस कार्यक्रम को अपने विचारों से समृद्ध बनाया। भारतवर्ष की आध्यात्मिक समृद्धि पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे इस तरह के मंच राष्ट्रीय एकता को और अधिक सुदृढ़ करते हैं।

काशी-तमिल संगमम का बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिला है। इसके जरिए जहां सांस्कृतिक चेतना को मजबूती मिली है, वहीं शैक्षिक विमर्श और जनसंवाद को भी काफी बढ़ावा मिला है। इससे हमारी संस्कृतियों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। इस मंच ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को आगे बढ़ाया है, इसलिए आने वाले समय में हम इस आयोजन को और वाइब्रेंट बनाने वाले हैं। ये वो भावना है, जो शताब्दियों से हमारे पर्व-त्योहार, साहित्य, संगीत, कला, खान-पान, वास्तुकला और ज्ञान-पद्धतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।

वर्ष का यह समय हर देशवासी के लिए बहुत ही पावन माना जाता है। लोग बड़े उत्साह के साथ संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल, माघ बिहू जैसे अनेक त्योहार मना रहे हैं। ये सभी उत्सव मुख्य रूप से सूर्यदेव, प्रकृति और कृषि को समर्पित हैं। ये त्योहार लोगों को आपस में जोड़ते हैं, जिससे समाज में सद्भाव और एकजुटता की भावना और प्रगाढ़ होती है। इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन उत्सवों के साथ हमारी साझी विरासत और सामूहिक भागीदारी की भावना देशवासियों की एकता को और मजबूत करेगी। ■





सहयोग से सशक्त होती भारत-जर्मनी भागीदारी

भारत और जर्मनी के बीच संबंध केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आज यह साझेदारी वैश्विक शांति, आर्थिक स्थिरता और तकनीकी नवाचार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। लोकतांत्रिक मूल्य, नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद में साझा विश्वास ने दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार बनाया है। दो दिवसीय जर्मन चांसलर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के साझा भविष्य पर लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय...

भारत-जर्मनी के संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 और 13 जनवरी को भारत की यात्रा पर रहे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे के बीच अहमदाबाद में हुई भारत-जर्मनी सीईओ फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी पहली एशिया यात्रा के लिए चांसलर मर्ज ने भारत को अपना डेस्टिनेशन बनाया। यह जर्मनी की डायवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में भारत की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। डिफेंस की दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सहयोग और गहरा करेगी। सेमीकंडक्टर में दोनों देश म्युचुअल पार्टनर हैं। इसके साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, फिनटेक, फार्मा, क्वांटम और साइबर, ऐसे क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। इंडिया-जर्मनी पार्टनरशिप न केवल म्युचुअल बेनिफिशियल है, बल्कि ये दुनिया के लिए भी बेहतर है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर,

इन विषयों पर विस्तार से हुई बात

रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, विज्ञान और अनुसंधान, हरित एवं सतत विकास साझेदारी/नवीकरणीय ऊर्जा, भारत-प्रशांत, कनेक्टिविटी और वैश्विक मुद्दे, शिक्षा, कौशल विकास, गतिशीलता और संस्कृति।

विंड और बायोफ्यूल में वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें जर्मन कंपनी के लिए सोलर सेल्स, इलेक्ट्रोलाइजर, बैटरी और विंड टरबाइन जैसे क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के बहुत अवसर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत का ऑल इंकलूसिव विजन है, जब जर्मनी का एआई इकोसिस्टम इससे जुड़ता है, तो हम एक ह्यूमन सेंट्रिक डिजिटल फ्यूचर सुनिश्चित कर सकते हैं।

एक नजर...

- खेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच ठोस कदम उठाए गए।
- उच्च शिक्षा पर एक व्यापक रोडमैप तैयार करने पर बात बनी, इससे शिक्षा के क्षेत्र में नई साझेदारी बनेगी।
- जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैम्पस खोलने के लिए आमंत्रित किया गया है।
- भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-फ्री ट्रांजिट की घोषणा जर्मनी की ओर से की गई है।
- गुजरात के लोथल में बन रहे नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से जर्मन मैरिटाइम म्यूजियम जुड़ेगा।
- ट्रेडिशन मेडिसिन के क्षेत्र में गुजरात आयुर्वेद युनिवर्सिटी का जर्मनी के साथ सहयोग बढ़ेगा।

जर्मन चांसलर मर्ज के साथ संयुक्त बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत, जर्मनी के साथ अपनी मित्रता एवं साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले वर्ष भारत-जर्मनी ने अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए हैं। इस वर्ष दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन केवल समय की उपलब्धियां नहीं हैं, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक हैं। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने दोनों देशों के बीच स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर 50 बिलियन डॉलर को पार कर गया है।

रिन्यूबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान हैं। इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने इंडियन-जर्मन सेंटर फॉर एक्सिलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का साझा मंच बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट, भविष्य की ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। दोनों देशों ने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप पर भी काम करने का निर्णय लिया है जिससे, को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे।

भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप पर जारी संयुक्त वक्तव्य इसी भरोसे का प्रतीक है। इससे खासतौर पर हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। दोनों देशों



जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और पतंग महोत्सव में भाग लिया।

की दोस्ती का प्रभाव ग्लोबल स्टेज पर भी दिखाई देता है। घाना, कैमरून और मलावी जैसे देशों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट से ट्राइलैटरल विकास साझेदारी दुनिया के लिए एक सफल मॉडल है। दोनों देशों ने ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए अपने साझा प्रयासों को निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है जिसके लिए दोनों देश एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं।

दोनों देशों ने यूक्रेन व गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। दोनों देश इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए जी-4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। ■

भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस : 1 फरवरी 2026

समुद्र प्रताप

सागर में भारत की स्वदेशी शक्ति

भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी, 2026 को 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस बार का स्थापना दिवस कुछ खास है क्योंकि भारत की एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति भारतीय तटरक्षक बल को मिली है। यह बेड़े का सबसे बड़ा और देश का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत 'समुद्र प्रताप' है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी, 2026 को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में 'समुद्र प्रताप' को शामिल किया। यह पोत आत्मनिर्भर भारत और भारतीय तटरक्षक बल की बढ़ती ताकत का है प्रतीक...



आधुनिक सुविधाओं से लैस भारत की समुद्री शान



'समुद्र प्रताप' भारतीय तटरक्षक बल का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है।



आत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित इस पोत में 30 मिमी सीआरएन-91 तोप, एकीकृत अग्नि नियंत्रण प्रणाली से लैस दो 12.7 मिमी स्थिर रिमोट-नियंत्रित तोपें हैं।



114.5

मीटर लंबा

16.5

मीटर चौड़ा



22

समुद्री मील से अधिक है गति

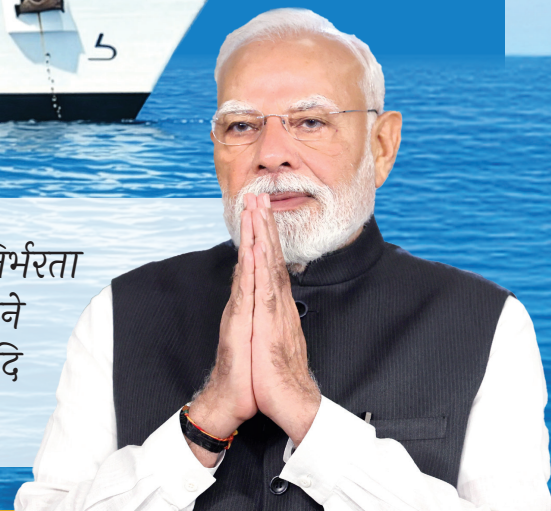


4,200

टन वजन है इसका

“

भारतीय तटरक्षक पोत 'समुद्र प्रताप' की कमीशनिंग हमारे आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को मजबूती देने, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्थायित्व के प्रति हमारी वचनबद्धता को प्रतिबिंबित करने आदि सहित अनेक कारणों से उल्लेखनीय है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 01-15 फरवरी, 2026
आरएनआई DELHIN/2020/78812 (प्रकाशन तिथि- 19 जनवरी 2026, कुल पृष्ठ-62)

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक
कंचन प्रसाद
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो
सूचना भवन, द्वितीय तल
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित